04 - रिकॉर्ड मतदान किसके लिए फायदेमंद

05 - राजा हिरदेशाह लोधीः बुन्देला विद्रोह के विस्मृत महानायक

06 - भीषण गर्मी भी नहीं रोक पाई आस्था, सैकड़ों गौभक्तों की मौजूदगी...

07 - सहकारी बैंकिंग और नई कृषि तकनीक से सशक्त बनें किसान...

A Daily News Magazine

भोपाल

मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 235, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

'आप' में बगावतः पंजाब में रंग लाएगा सियासी भूचाल

जगदीप सिंधु

पंजाब से आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में चले गए। एक के खिलाफ तो चंद दिनों पहले ईडी के छापे भी पड़े थे। इस घटनाक्रम से पंजाब में सियासी भूचाल आ गया है। पंजाब में राजनीतिक घटनाक्रम की करवटों ने सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को सकते में डाल दिया है। पंजाब की सियासत में भूचाल जैसी स्थिति बन गई है। आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सदस्यों ने कल दिल्ली में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी को अलविदा कहकर भारतीय जनता पार्टी को अपना नया आश्रय स्थल बनाने की घोषणा कर दी। आम आदमी पार्टी में एक बड़ी बगावत अब धरातल पर स्पष्ट हो गई है। पूरी पार्टी के अस्तित्व के साथ-साथ उसकी सरकार पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं।

आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेताओं में से राघव चड्ढा, जिन्हें अरविंद केजरीवाल का करीबी माना जाता है, के साथ संदीप पाठक, अशोक मित्तल (लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक) तथा चार अन्य राज्यसभा सदस्य–विक्रमजीत सिंह साहनी, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता और दिल्ली से स्वाति मालीवाल ने पार्टी छोड़ने के निर्णय को सार्वजनिक कर आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया के पास इस टूट को बचाने का कोई अवसर नहीं बच पाया। इसे पार्टी की छवि के लिए बड़ा आघात माना जा रहा है और उसके नेतृत्व व अस्तित्व पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया में केवल इतना ही कह पाए– 'बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ धक्का किया।' लेकिन वे यह नहीं बता सके कि ऐसी स्थिति क्यों बनी, जिसमें पार्टी का एक बड़ा हिस्सा अलग होकर भाजपा में शामिल हो गया। राघव चड्ढा ने सीधे तौर पर पूरी पार्टी को 'भ्रष्ट और समझौतापरस्त' बताया है, जिसका प्रभावी जवाब अरविंद केजरीवाल नहीं दे पाए। 'ऑपरेशन लोटस' की आड़ में अपने कृत्य को ढंकने के प्रयासों में अब पार्टी लगी हुई है। राघव चड्ढा ने कहा है कि अब हर झूठ को उजागर किया जाएगा और हर प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा।

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में 10 सदस्य हैं, जिनमें से सात पंजाब से और तीन दिल्ली कोटे से हैं। वर्तमान में पार्टी की संख्या और स्थिति राज्यसभा में पूरी तरह बदल गई है। पंजाब कोटे के सात सदस्यों में से अब केवल संत बलबीर सिंह सींचेवाल ही पार्टी के प्रतिनिधि बचे हैं, जबकि दिल्ली कोटे से संजय सिंह और एन. डी. गुप्ता बचे हैं। राघव चड्ढा ने कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ङ्क पर पोस्ट कर संकेत दिया था- 'घायल हूं, इसलिए घातक हूं।' इस घटना ने पार्टी की आंतरिक कलह और वर्चस्व की लड़ाई को सतह पर ला दिया है। स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी की राजनीति जनता के सरोकारों से अधिक अपनी निहित राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और स्वार्थों पर आधारित है।

यह फूट अचानक नहीं हुई है। इसके पीछे लंबे समय से कई कारण सक्रिय थे। राघव चड्ढा को हाल ही में राज्यसभा में उपनेता के पद से हटाकर उनकी जगह अशोक मित्तल को नियुक्त किया गया था। राघव चड्ढा और अन्य सदस्यों के मतभेद पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से काफी समय से सामने आ रहे थे। इन नेताओं ने पार्टी पर अपने मूल सिद्धांतों से भटकने का आरोप लगाया और आंतरिक असंतोष को सार्वजनिक कर दिया। इस घटनाक्रम ने पार्टी और उसके नेतृत्व की विश्वसनीयता को गहरा आघात पहुंचाया है।

पंजाब में इस पूरी घटना को निराशाजनक दृष्टि से देखा जा रहा है और आम जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इसका आक्रोश आने वाले समय में ज़मीन पर दिखाई दे सकता है। जिन पारंपरिक राजनीतिक दलों को खारिज करने के अभियान के दम पर आम आदमी पार्टी ने सत्ता हासिल की थी, वह तिलिस्म भी अब टूटता नजर आ रहा है। इस घटना ने मुख्य विपक्षी दलों की राजनीतिक विश्वसनीयता को फिर से स्वीकार्यता मिलने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इस बड़ी फूट ने जहां आम आदमी पार्टी को कमजोर किया है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और अकाली दल को आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बड़ी राहत दी है।

भारतीय जनता पार्टी अपने लंबे समय से पिछड़े लक्ष्य को साकार होते देख उत्साहित है, लेकिन पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत करना उसके लिए आसान नहीं होगा। आम आदमी पार्टी में सेंध लगाने में सफलता मिलने के बावजूद जनमानस के आक्रोश को समर्थन में बदलना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। पंजाब में भाजपा को अभी व्यापक स्वीकार्यता हासिल नहीं है। छल-कपट और कुटिल राजनीति को पंजाब की आबोहवा अक्सर नकार देती है या उसका पर्दाफाश हो जाता है, जैसा कि आम आदमी पार्टी के साथ हुआ है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटनाक्रम से आगामी विधानसभा चुनावों में 'खंडित जनादेश' की स्थिति बन सकती है, जिससे पंजाब राजनीतिक अस्थिरता और खरीद-फरोख्त का केंद्र बन सकता है। आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के भीतर गहरी दरारें उजागर हुई हैं, जो अरविंद केजरीवाल के मजबूत एकता के दावों के विपरीत हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दलबदलुओं को 'गद्दार' बताया और कहा कि उनके जाने से पार्टी की जमीनी ताकत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि, पार्टी की आंतरिक बैठकों में लगभग 70 विधायकों के टिकट काटने की चर्चाओं से संकेत मिलता है कि गिरते जनाधार को संभालना मुश्किल होता जा रहा है। राघव चड्ढा की छवि पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान ही धूमिल हो चुकी थी, जब उन पर टिकट बेचने के आरोप लगे थे। आम आदमी पार्टी पहले ही पंजाब में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन अब यह संकट और भी गहरा हो गया है।

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

एमपी विधानसभा में महिला आरक्षण पर तकरार, कांग्रेस विधायकों ने किया वॉकआउट

नारी-शक्ति वंदनः सीएम बोले- 'महिलाओं का हक कांग्रेस ने रोका'

विपक्ष ने कहा- अभी लागू करो 33% आरक्षण, परिसीमन का इंतजार क्यों?

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में 'नारी शक्ति वंदन' पर चर्चा के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव के बयान और उस पर विपक्ष के तीखे जवाब ने सियासी माहौल गरमा दिया है। सीएम ने जहां कांग्रेस पर महिलाओं का हक रोकने का आरोप लगाया, वहीं विपक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर नीयत साफ है तो 33% आरक्षण तुरंत लागू किया जाए, परिसीमन का इंतजार क्यों।

सीएम बोले-कांग्रेस ने ठोस कदम नहीं उठाए- मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने संबोधन की शुरुआत सांस्कृतिक संदर्भों से करते हुए महिला शक्ति के महत्व पर जोर दिया, लेकिन जल्द ही उन्होंने कांग्रेस पर सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए।

आधी आबादी के साथ अन्याय किया- सीएम ने कहा कि इतिहास में कई बार ऐसे मौके आए, जब महिलाओं को बराबरी देने के फैसले लिए जा सकते थे, लेकिन परिसीमन को रोककर और संवैधानिक बदलावों के जरिए उनके अधिकारों का रास्ता रोका गया। उन्होंने इसे 'आधी आबादी के साथ अन्याय' करार देते हुए कहा कि इसका जिम्मेदार कांग्रेस का राजनीतिक रवैया है।

नेता प्रतिपक्ष ने पूछा-कब लागू करेंगे ये बताओ?

इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार को घेरते हुए कहा कि महिला आरक्षण को लेकर सरकार स्पष्ट जवाब दे कि इसे लागू कब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज आरक्षण चाहती हैं, 2029 या 2047 में नहीं। अगर सरकार की मंशा साफ है तो मौजूदा व्यवस्था में ही इसे लागू किया जाना चाहिए।

सीएम ने कहा- बिना संविधान संशोधन ये संभव नहीं- सीएम ने अपने भाषण में यह भी कहा कि बिना संविधान संशोधन और परिसीमन के महिला आरक्षण लागू करना संभव नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का रवैया हमेशा विरोध का रहा है–सत्ता में रहते हुए भी और विपक्ष में रहते हुए भी।

मुख्यमंत्री ने आंकड़ों के जरिए तर्क देते हुए कहा कि अगर समय पर निर्णय लिए जाते तो आज लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की संख्या दोगुनी से ज्यादा हो सकती थी। उन्होंने दावा किया कि सीटों की संख्या बढ़ने पर महिलाओं को बड़ा प्रतिनिधित्व मिलता और वंचित वर्गों की महिलाओं को भी ज्यादा अवसर मिलते।

लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी सीमित- सीएम ने कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर 33% आरक्षण का 'हक छीनने' का आरोप लगाते हुए कहा कि संसद में यह मौका गंवा दिया गया। उन्होंने कहा कि आज लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी सीमित है, जबकि यह संख्या कहीं ज्यादा हो सकती थी। इस पर विपक्ष ने फिर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार सिर्फ भविष्य की बात कर रही है, जबकि महिलाओं को वर्तमान में अधिकार चाहिए।

भारत-न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन

- दोनों देशों के बीच एक्सपोर्ट पर ड्यूटी जीरो हुई

अब 5000 भारतीयों को वर्किंग वीजा मिलेगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत-न्यूजीलैंड के बीच सोमवार को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) साइन हो गया है। अब भारत से न्यूजीलैंड भेजे जाने वाले लेदर प्रोडक्ट्स,टेक्सटाइल,प्लास्टिक और इंजीनियरिंग गुड्स जैसे सामानों पर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। जिससे इन श्रम-प्रधान क्षेत्रों यानी लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को सीधा लाभ होगा।

5 हजार भारतीय प्रोफेशनल्स को वर्किंग वीजा मिलेगा

सर्विस सेक्टर में भारत ने शिक्षा, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन और टूरिज्म जैसे हाई-वैल्यू सेक्टरों में बाजार पहुंच हासिल की है। समझौते के तहत , योगा इंस्ट्रक्टर्स, इंडियन शेफ और म्यूजिक टीचर्स के लिए भी रास्ते खुलेंगे। एफटीए में एक नया टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट एंट्री वीजा का रास्ता बनाया गया है।

न्यूजीलैंड को कृषि उत्पादों पर रियायत

डेयरी पर छूट नहीं

न्यूजीलैंड को भारतीय बाजार में पहुंच देने के लिए भारत ने अपनी 70 फीसदी टैरिफ लाइन्स खोल दी हैं। इसमें सेब, कीवी फ्रूट और मनुका हनी जैसे कृषि उत्पादों पर टैरिफ रियायतें दी गई हैं, लेकिन ये कोटा लिमिट और मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस की शर्तों के साथ होंगी। इसके अलावा न्यूजीलैंड को भारत में अपने 54 फीसदी से ज्यादा एक्सपोर्ट पर तुरंत शून्य ड्यूटी मिलेगी। इसमें शीप मीट, ऊन, कोयला और फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स शामिल हैं। सीफूड, आयरन, स्टील और एल्युमीनियम स्क्रैप पर टैरिफ को अगले 10 सालों में धीरे-धीरे खत्म करेंगे।

मैं 'आप' के साथ खत्म कर रहा हूं सफर...

- गुजरात में नतीजों से पहले केजरीवाल को झटका

अहमदाबाद (एजेंसी)। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों से पहले आम आदमी पार्टी (आप) को झटका लगा है। पार्टी के गुजरात प्रदेश महासचिव और किसान नेता सागर रबारी ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। सागर रबारी काफी वक्त से आप से जुड़े हुए थे। सागर रबारी ने ऐसे वक्त पर आप छोड़ी है जब एक दिन बाद यानी 28 अप्रैल को गुजरात स्थानीय निकाय चुनावों के रिजल्ट घोषित होने हैं। गुजरात में आप की कमान इसुदान गढ़वी के हाथों में है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के पूर्व मंत्री गोपाल राय को आप का प्रभारी बनाया हुआ है। उनके साथ दिल्ली के पूर्व विधायक गुलाब सिंह मटियाला भी मोर्चे पर हैं। सागरभाई रबारी ने अपने इस्तीफे का ऐलान एक फेसबुक पोस्ट से किया है। आप को यह झटका ऐसे वक्त पर लगा है जब आप अपने सात राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में जाने से बैकफुट पर है।

एएपी के सात सांसदों को बीजेपी में विलय की मंजूरी

- राज्यसभा में भाजपा सांसद 106 से बढ़कर 113 हुए

केजरीवाल की पार्टी 3 पर सिमटी

नई दिल्ली (एजेंसी)। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के सात बागी सांसदों के भाजपा में विलय को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद राज्यसभा में एएपी की संख्या घटकर 3 रह गई है, जबकि बीजेपी सांसदों की संख्या 106 से बढ़कर 113 हो गई है। जो सात सांसद बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनमें राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, विक्रमजीत साहनी, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता शामिल हैं। राज्यसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इन सांसदों को बीजेपी के सदस्यों के रूप में दिखाया गया है। एएपी ने रविवार को सभापति से सातों सांसदों की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी। संजय सिंह ने भी लेटर लिखकर उन्हें दलबदल कानून के उल्लंघन का दोषी बताते हुए अयोग्य घोषित करने की अपील की।

शरद की सुबह

स्त्रियों ने बचाए हैं
रसोई के किसी डब्बे में कुछ पैसे
आड़े वक्त की रसोई के लिए

आंगन में तुलसी बचाई है
पीपल बचाए हैं
चौक चबूतरे पर

स्त्रियों ने बचाया है
दरवाजों के किवाड़ों को
छत की दीवारों को
दीवारों में खिड़कियों को

घर में घर
रिश्तों में रिश्ते
और पुरुष में पुरुष को
स्त्रियों ने बचाया है

प्रश्नों का पानी बचाया है
मौन के बांध बनाकर
स्त्रियों ने

कभी-कभी
प्रेम न कर के भी
प्रेम को बचाया है
स्त्रियों ने।

- नरेश गुर्जर

पाकिस्तान में लश्कर के

आतंकी शेख यूसुफ की हत्या

- गोली मारकर की हत्या, 2026 में 30वां आतंकी बना निशाना

इस्लामाबाद (एजेंसी)। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर शेख यूसुफ अफरीदी की पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक हमलावरों ने अफरीदी पर कई राउंड गोलियां चलाई थी। अफरीदी लश्कर कमांडर हाफिज सईद का करीबी सहयोगी था और इस हमले के दौरान उसे भागने का कोई मौका नहीं मिला। अफरीदी को आतंकी संगठन लश्कर के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में होने वाले ऑपरेशन्स की एक अहम कड़ी माना जाता था। जांच एजेंसियां उसकी मौत को एक टारगेटेड हत्या यानि सोची-समझी साजिश के तहत की गई हत्या माना है। शेख यूसुफ अफरीदी की हत्या उसी कड़ी का हिस्सा है जिसके तहत पिछले दो सालों में पाकिस्तान में एक के बाद एक कई आतंकियों की हत्या की गई है।

- पाकिस्तान में एक के बाद एक वांटेड आतंकियों की हत्या- इससे पहले जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर के बड़े भाई मुहम्मद ताहिर अनवर की भी पाकिस्तान में संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। बताया जाता है कि उनकी मौत बेहद रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। अनवर जैश-ए-मोहम्मद के भीतर एक अहम भूमिका निभाता था और इस आतंकी ऑप रेशन्स में सक्रिय था।

- आम सहमति मुश्किल, भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष का किया समर्थन

मिडिल ईस्ट पर मतभेद के कारण मुश्किल हुई ब्रिक्स की राह

नई दिल्ली (एजेंसी)। पिछले हफ्ते मिडिल-ईस्ट पर हुई ब्रिक्स की बैठक में कोई आम सहमति वाला दस्तावेज तैयार नहीं हो सका, क्योंकि इस संघर्ष में शामिल सदस्य देशों के रुख में काफी मतभेद थे। भारतीय अधिकारियों के अनुसार, बाकी सभी देशों द्वारा इन मतभेदों को दूर करने की कोशिशें कामयाब नहीं हो सकीं। इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है और वह अगले महीने विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। इसके बाद इसी साल के अंत में शिखर सम्मेलन होगा। आम सहमति न बन पाने के कारण पिछले हफ्ते विदेश मंत्रियों और विशेष दूतों की बैठक में कोई संयुक्त बयान जारी नहीं हो सका। इसके बजाय अध्यक्ष का बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि सदस्य देशों ने मिडिल-ईस्ट में हाल ही में हुए संघर्ष पर गहरी चिंता जताई और इस मामले पर अपने विचार और आंकलन पेश किए। चर्चाओं में फलस्तीन का मुद्दा और गाजा की स्थिति शामिल थी, जिसमें मानवीय सहायता पहुंचाना, ब्रिक्स की भूमिका, आतंकवाद के प्रति जीरो-टॉलरेंस का रवैया अपनाना और लेबनान में संघर्ष-विराम का स्वागत करना है।

फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत का रुख हमेशा से स्पष्ट रहा है

एक सूत्र ने कहा, फलस्तीन मुद्दे पर भारत ने अभी हाल ही में 26 जनवरी को अरब लीग (जिसमें फलस्तीन भी शामिल है) के साथ एक साझा सहमति वाला रुख अपनाया था। भारत दो-राष्ट्र समाधान के अपने समर्थन को लेकर हमेशा से स्पष्ट रहा है। सूत्र ने आगे बताया कि ब्रिक्स समूह के कई देशों ने शर्म अल-शेख शांति शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स के प्रस्ताव 2803 का समर्थन किया था। इस प्रस्ताव में गाजा में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक व्यापक 20-सूत्रीय शांति योजना का अनुमोदन किया गया था, जिसमें शांति बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव भी शामिल था।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c

न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ मंगलवार, 28 अप्रैल 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

संक्षिप्त समाचार

अब नहीं होगी दवाओं की अवैध ऑनलाइन बिक्री

● बिक्री पर रोक के लिए एनसीबी ने बनाया मास्टर प्लान

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत में कुछ दवाओं को बिना डाक्टर की पर्ची या प्रेसक्रिप्शन के खरीदा बेचा नहीं जा सकता है, लेकिन अवैध तरीके से इन दवाओं की आनलाइन खरीद बिक्री बड़ी समस्या है। दवाओं की ऑनलाइन तस्करी के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने रविवार को समन्वित आपरेशन-वाइप - शुरू किया और आनलाइन तस्करी के 122 मामलों की पहचान की। एनसीबी ने एक बयान में कहा कि उसने वेब बेस्ड इलिसिट एक्टिविटीज

प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर कार्रवाई

एनसीबी आपरेशन वाइप चलाने के लिए अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड (आईएनसीबी) के खुफिया प्लेटफार्म एसएनओओपी (स्कैनिंग नोवेल ओपिओइड्स ऑन ऑनलाइन प्लेटफार्म्स) के नाम से जाना जाता है की मदद ले रही है। यह पहल आपरेशन मेड-मैक्स की सफलता पर आधारित है, जिसे एनसीबी ने अमेरिकी डीईए, आस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस (एएफपी) और कुछ अन्य विदेशी एजेंसियों के साथ मिलकर जुलाई 2025 में अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी गिरोह को खत्म करने के लिए चलाया था।

प्रिंवेशन एंड इंफोर्समेंट (वाइप) के तहत कुछ आनलाइन प्लेटफार्मों को नोटिस जारी किए हैं, जिसमें उन्हें तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रापिक सब्सटेंसेस एक्ट) के तहत विनियमित उत्पादों की सूची साझा की गई है ताकि ऐसी सूचियों की पहचान और उन्हें हटाने में मदद मिल सके। इस संबंध में इंडिया मार्ट, ट्रेडइंडिया और डायल-ट्रेड जैसे आनलाइन प्लेटफार्म ने कुछ उपाय किए हैं, जिनमें संदिग्ध विक्रेताओं को निलंबित करना शामिल है।

राष्ट्रपति मुर्मू शिमला पहुंचीं गवर्नर-सीएम ने किया स्वागत

● अटल टनल रोहतांग और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर भी जाएंगी

अगले 5 दिन यहीं रुकेंगी

शिमला (एजेंसी)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को शिमला पहुंच गई हैं। उनका हेलीकॉप्टर छराबड़ा स्थित कल्याणी हेलिपेड पर उतरा। इस दौरान हिमाचल के गवर्नर कविंदर गुप्ता, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू व अन्य ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति के काफिले में तीन हेलीकॉप्टर दिल्ली से शिमला पहुंचे। इनमें से एक हेलीकॉप्टर छराबड़ा और दो हेलीकॉप्टर अन्नाडेल में लैंड किए। राष्ट्रपति मुर्मू पांच दिन के हिमाचल दौरे पर आई हैं। वह शिमला से लगभग 13 किलोमीटर दूर छराबड़ा स्थित राष्ट्रपति भवन रिट्रीट में रुकी

हैं। शिमला पुलिस ने राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। शिमला शहर से लेकर छराबड़ा तक 1000 पुलिस जवान तैनात कर रखे हैं। द्रौपदी मुर्मू अगले पांच दिन हिमाचल में रुकेंगी। 28 अप्रैल को राष्ट्रपति हिमाचल के राज्यपाल द्वारा लोक भवन शिमला में आयोजित भोज (बैंकेट) में शामिल होंगी। 29 अप्रैल को राष्ट्रपति अटल टनल रोहतांग का दौरा करेंगी। 30 अप्रैल को राष्ट्रपति पालमपुर स्थित विवि के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी।

● पीएम मोदी के 'झालमुड़ी ब्रेक' का दिया जवाब

फल और सब्जियां खरीदती दिखीं ममता बनर्जी

कोलकाता (एजेंसी)। बंगाल के चुनावी माहौल के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रविवार को एक बार फिर अपने अलग अंदाज में नजर आईं। अपने विधानसभा क्षेत्र कोलकाता के भवानीपुर में पदयात्रा और चुनावी जनसभाओं के बाद ममता अचानक स्थानीय सब्जी बाजार पहुंच गईं और खरीदारी करती दिखीं। अपनी सादगी के लिए जानी जाने वालीं ममता का यह कदम ऐसे समय में सामने आया है, जब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का बंगाल के झाड़ग्राम में चुनावी रैली के बाद एक छोटी सी दुकान से 'झालमुड़ी ब्रेक' चर्चा में रहा था। ऐसे में ममता का सब्जी और फल खरीदना भी राजनीतिक हलकों में एक प्रतीकात्मक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।

बाजार में 'दीदी' का अपनापन

करीब 71 वर्षीय ममता ने बाजार में सब्जियों के साथ-साथ फलों की भी खरीदारी की और लोगों से घुल-मिलकर बातचीत की। 'दीदी-दीदी' के नारों के बीच उन्होंने लोगों से हाथ मिलाया, मालाएं स्वीकार कीं और अपने सुरक्षा कर्मियों को भीड़ को दूर न करने की हिदायत दी। यह दृश्य उनके जमीनी और सादगीपूर्ण राजनीतिक स्टाइल को एक बार फिर सामने लाता है। दीदी, दीदी के नारों के बीच उन्होंने लोगों से हाथ मिलाया, मालाएं लीं और अपने सुरक्षाकर्मियों को उन लोगों को हटाने से रोक दिया, जो उनके पैर छूने के लिए उमड़ पड़े थे।

राहुल का सवाल-आपका सबसे जोखिम काम क्या है

● डीयू की छात्रा ने दिया तगड़ा जवाब-कांग्रेस से जुड़ना

छात्रा ने कांग्रेस में शामिल होने को बताया जोखिम

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्राओं के साथ संवाद कर रहे हैं। इस दौरान एक पल ऐसा भी आया जब एक लड़की के जवाब ने वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया। बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने छात्राओं से पूछा कि उन्होंने अब तक सबसे जोखिम भरा काम कौन सा किया है, इस पर एक लड़की ने व्यंगात्मक अंदाज में जवाब दिया, कांग्रेस में शामिल होना। छात्रा का जवाब सुनकर वहां मौजूद सभी लोग ठहाका लगाकर हंसने लगे। छात्रा का जवाब कांग्रेस की मौजूदा स्थिति पर एक तंज था। इस पर कांग्रेस नेता ने कहा कि यह वाकई जोखिम भरा है। एजुकेशन सिस्टम पर बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब बीजेपी हारेगी, तो भारत को कुछ तत्वों को हटाने के लिए एक-एक करके सभी संस्थाओं से गुजरना होगा। जैसे कि शिक्षा व्यवसाय में, हम किसी एक विचारधारा के लोगों को हर चीज तय करने की अनुमति नहीं देंगे।

उप मुख्यमंत्री ने बसामन मामा गौवंश वन्य विहार में किया रात्रि विश्राम, सुबह व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण

भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने गत रात्रि बसामन मामा गौवंश वन्य विहार के रेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम किया। उप मुख्यमंत्री ने सुबह भ्रमण के दौरान गौवंश वन्य विहार की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों व व्यवस्थापकों को व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ व व्यवस्थित करने के निर्देश दिये। उन्होंने प्राकृतिक खेती सहित गौवंश के लिये भूसा-चारा आदि की व्यवस्था के संबंध में पूंछताछ की। इस दौरान पूर्व उप संचालक पशुपालन विभाग डॉ. राजेश मिश्रा सहित व्यवस्थों से संबंधित जन उपस्थित रहे।

उप मुख्यमंत्री ने थल सेना अध्यक्ष का रीवा एयरपोर्ट में किया स्वागत

भोपाल। भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदी वायुसेना के विशेष विमान से रीवा एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट में उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने थल सेना अध्यक्ष का पुष्पगुच्छ भेंटकर आत्मीय स्वागत किया।

महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सजग, विपक्ष को सिखायेंगी सबक: अश्विनी परांजपे

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती अश्विनी परांजपे ने सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में महिला मोर्चा 28 अप्रैल, मंगलवार को भोपाल में मशाल जुलूस निकालेगा। मशाल जुलूस में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक श्री हेमंत खण्डेलवाल, मध्यप्रदेश शासन की महिला मंत्री, सांसद एवं विधायक बहनें, महिला मोर्चा की पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बहनें शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि सोमवार को महिला मोर्चा की बहनों ने विधानसभा के विशेष सत्र की कार्यवाही का अवलोकन कर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को समझा। महिला नेत्रियों ने संकल्प लिया कि सभी बहनें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए देश की आधी आबादी को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगी।

मशाल जुलूस में शामिल होंगे मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व पदाधिकारी बहनें- भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती अश्विनी परांजपे ने कहा कि मंगलवार 28 अप्रैल को सायं 5 बजे महिला मोर्चा द्वारा भोपाल में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। मशाल जुलूस सोमवारा पुलिस चौकी से प्रारंभ होकर सुभाष चौक होते हुए लखेरापुरा पहुंचेगा। मशाल जुलूस में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक श्री हेमंत खण्डेलवाल, मध्यप्रदेश शासन की महिला मंत्री, सांसद व विधायक बहनें, महिला मोर्चा की पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होंगी। इस आयोजन के माध्यम से महिला मोर्चा यह संदेश देगा कि मध्यप्रदेश सहित देश की बहनें अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं और महिलाओं के अधिकारों में रोड़ा अटकाने वाले विपक्षी दलों को देश की नारी शक्ति सबक सिखाने को तैयार है।

महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सजग, विपक्षी दलों को सिखाएंगी सबक- भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती अश्विनी परांजपे ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए लाए गए 'नारी शक्ति वंदन' अधिनियम का विरोध महिलाओं के अधिकार और सम्मान का हनन है। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने संसद में इस अधिनियम को पारित नहीं होने दिया। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने 'नारी शक्ति वंदन' अधिनियम का विरोध कर महिलाओं का अधिकार छीना है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाकर देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का बड़ा प्रयास था, जिसे कांग्रेस और विपक्षी दलों ने पूरा नहीं होने दिया।

प्रचंड गर्मी, आसमान से बरस रहे आग के शोले

● दिल्ली-यूपी एमपी और राजस्थान में आग उगल रहा पारा ● महाराष्ट्र के अकोला में पारा 46.9 ,देश में सबसे गर्म रहा

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रचंड गर्मी ने पूरे भारत की नींद उड़ा रखी है। अप्रैल में ही देश के कई जगहों पर पारा 40 डिग्री के पार चला गया है। वहीं, देश अभी से ही भीषण लू चलने लगी है, जिससे देश के कई शहर बेहद गर्म हो गए हैं। भारतीय मौसम विभाग ने हीटवेव यानी लू को लेकर चेतावनी दी है कि यह स्थिति उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले तीन दिनों तक बनी रहेगी। हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ क्षेत्र, बिहार और गुजरात में यही हालात बने रहने वाले हैं। एजेंसी के अनुसार, झांसी, ओरछा और बालनगीर भारत के सबसे गर्म शहरों में से हैं। वहीं, विंडीडॉट कॉम के

अनुसार, सोमवार दोपहर तक नई दिल्ली, अहमदाबाद और गुना का तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया था।

बिहार में गर्मी से 2 और आंधी-बिजली से 5 मौतें- देश में भीषण गर्मी जारी है। राजस्थान, यूपी और महाराष्ट्र के 7 शहरों में रविवार को तापमान 46 डिग्री के पार चला गया। महाराष्ट्र का अकोला 46.9 डिग्री के साथ देश में सबसे गर्म रहा। अमरावती 46.8, बांदा 46.6, वर्धा और बाड़मेर 46.4, जैसलमेर और यवतमाल 46 डिग्री तापमान के साथ हीटवेब की चपेट में हैं। यूपी के 60 जिलों में लू का अलर्ट है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में पहली बार तापमान 45 डिग्री पहुंचा। इंदौर-भोपाल में भी पारा 43 डिग्री पर बना हुआ है। उत्तराखंड के देहरादून में गर्मी के चलते 12वीं तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बिहार के 8 जिलों में रविवार को पारा 40 डिग्री के पार चला गया। यहां गर्मी से दो मौतों की खबर है। नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में आंधी और बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के सबसे 100 गर्म शहरों में से 95 शहर भारत में ही हैं। इसमें मध्य भारत से होकर गंगा के मैदानों तक कई शहरों में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं, कहीं-कहीं यह 45 डिग्री के पास पहुंच सकता है।

● पुतिन और मोदी ने चीन-अमेरिका को दिए पांच बड़े संदेश

भारत-रूस की नई सैन्य डील से दहशत में दुनिया !

मॉस्को/नई दिल्ली (एजेंसी)। रूस के लीगल इन्फॉर्मेशन पोर्टल ने हाल ही में भारत के साथ पिछले साल हुए लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के आपसी आदान-प्रदान यानि रीलोज सैन्य लॉजिस्टिक्स समझौते की जानकारी दी है। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे के देश में 3000 सैनिक, 10 लड़ाकू विमान और पांच युद्धपोतों की तैनाती कर सकेंगे। भारत और रूस के बीच किए गये इस सैन्य समझौते की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। रूसी समाचार एजेंसी से बात करते हुए भारत के पूर्व एयर मार्शल अनिल चोपड़ा (सेवानिवृत्त) ने लिखा है कि इस समझौते से भारत और रूस ने दुनिया को पांच अहम संदेश दिए हैं। रीलोज समझौता क्या है- इस समझौते के तहत भारत और रूस की थल सेना, नौसेना और वायु सेना एक-

दूसरे के सैन्य अड्डों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों का उपयोग कर सकेंगी। इस समझौते के तहत दोनों देश ईंधन, राशन, मरम्मत सेवाएं, स्पेयर पार्ट्स और रखरखाव जैसी सुविधाओं के लिए एक-दूसरे के नेटवर्क का इस्तेमाल कर पाएंगे।

बंदरगाहों तक पहुंच मिलेगी जिससे उसकी रणनीतिक पहुंच बढ़ेगी- इसके अलावा इस समझौते के तहत भारत को रूस के आर्कटिक (जैसे मरमंस्क) और सुदूर पूर्व (जैसे व्लादिवोस्तोक) के बंदरगाहों तक पहुंच मिलेगी जिससे उसकी रणनीतिक पहुंच बढ़ेगी। भारत-रूस बने हुए हैं रणनीतिक साझेदार- पूर्व एयर मार्शल अनिल चोपड़ा ने बताया है कि पेपे एस्कोबार ने मार्च में झूठा दावा किया था कि भारत ने रूस के साथ विश्वासघात किया है लेकिन रीलोज समझौते के बाद यह बात सच्चाई से कोसों दूर साबित होती है। इस समझौते के जरिए हिंद महासागर क्षेत्र में रूस की शीत युद्ध के दौर वाली स्थायी सैन्य मौजूदगी फिर से बहाल हो गई है। इसी तर अगर भारत चाहे तो अब उसे रूसी सुदूर पूर्व और आर्कटिक क्षेत्र में भी एक अभूतपूर्व स्थायी सैन्य मौजूदगी हासिल हो जाएगी जो उनकी विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की मजबूती का प्रतीक है। इसलिए उनके बीच किसी भी तरह की दरार को लेकर लगाई जा रही अटकलें पूरी तरह से गलत हैं।

रूस चीन को आर्कटिक पर हावी नहीं होने देगा

मॉस्को ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि रूस चीन का जागीरदार नहीं है तो ये देश वहां बड़े पैमाने पर निवेश करने में ज्यादा सहज महसूस कर सकते हैं। रूस चीन को आर्कटिक पर हावी नहीं होने देगा- सीएनएन के साथ साथ कई मीडिया आउटलेट्स लंबे समय से यह डर फैलाते रहे हैं कि रूस चीन का पिछलग्गू बनकर उसे आर्कटिक पर हावी होने देगा और इसीलिए रूस के लिए इस क्षेत्र का सैन्यीकरण करना बेहद जरूरी है। रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा ने लिखा है कि यह बात कभी भी विश्वसनीय नहीं थी और अब रीलोज के कारण यह पूरी तरह से गलत साबित हो गई है। क्योंकि रीलोज पश्चिमी देशों के अनुकूल भारत को अगर वह चाहे तो, वहां अपनी सैन्य मौजूदगी स्थापित करने की अनुमति देता है।

अमेरिका से तनाव के बीच मास्को पहुंचे अराघची

● राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे ईरानी विदेश मंत्री

मॉस्को (एजेंसी)। अमेरिका से तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री सैय्यद अब्बास अराघची सोमवार को रूस पहुंचे। उनका रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने की संभावना है। उनका दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका के साथ युद्धविराम टूटने की आशंका है। ईरान ने पाकिस्तान में अमेरिकी अधिकारियों से मिलने से मना कर दिया था। ईरान के विदेश मंत्रालय ने टेलीग्राम पर बताया कि अब्बास अराघची सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे हैं जहां उनके रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने की उम्मीद है। यह घटनाक्रम तब सामने आया जब अराघची ने इस्लामाबाद की यात्राओं के बीच ओमान का भी दौरा किया। मध्यस्थ तेहरान और वॉशिंगटन के बीच शांति वार्ता को जीवित रखने की कोशिशों में जुटे हैं।

बंगाल की क्लीन चिट पर एमपी पुलिस को शक

3278 संदिग्धों में से 3259 को बताया भारतीय,अब फिर होगी चेकिंग

भोपाल। मध्य प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों और बंगाल सरकार के बीच दस्तावेजी दांवपेच शुरू हो गए हैं। पिछले साल केंद्र के निर्देश पर एमपी पुलिस ने जिन 3,278 लोगों को संदिग्ध बांग्लादेशी मानकर चिह्नित किया था, उनमें से 3,259 को पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना नागरिक स्वीकार कर लिया है। बंगाल प्रशासन का कहना है कि इन लोगों के आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी उनके ही राज्य से जारी हुए हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती; एमपी का गृह विभाग इस क्लीन चिट को पूरी तरह स्वीकार करने के मूड में नहीं है।

20 टीमें, 30 जिले और एक बड़ा संदेह- मुख्य सचिव अनुराग जैन के नेतृत्व में बनी रणनीति के तहत एमपी पुलिस की 20 टीमों ने बंगाल के सरकारी दफ्तरों की खाक छानी। जांच में पाया गया कि सिर्फ 19 लोगों के दस्तावेज फर्जी थे, जिन्हें तुरंत बीएसएफ को सौंपकर सीमा पार भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। बाकी 3,259 लोगों को बंगाल ने अपना माना, लेकिन एमपी पुलिस के अधिकारियों का तर्क है कि संभव है कि घुसपैठियों ने बंगाल पहुंचकर वहां से फर्जी तरीके से असली दस्तावेज बनवा लिए हों।

भाषा और काम बना था पहचान का आधार

यह पूरा अभियान जून 2025 में केंद्र के निर्देश के बाद शुरू हुआ था। सभी थाना प्रभारियों को निर्देश थे कि वे अपने इलाकों में संदिग्धों की भाषा, काम करने के तरीके और रहन-सहन के आधार पर उन्हें चिह्नित करें। इसी आधार पर 3,278 लोगों की लिस्ट तैयार हुई थी। अब गृह विभाग का कहना है कि सत्यापन एक सतत प्रक्रिया है और संदेह होने पर दोबारा जांच कराई जा सकती है।

स्कूल शिक्षा विभाग में पहले पदोन्नति फिर ट्रांसफर

हाईकोर्ट का आदेश-30 दिन में कार्रवाई पूरी करें, संगठन बोले-गलत क्रम से बढ़ सकता है विवाद

भोपाल। जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग में पदोन्नति, स्थानांतरण और अतिशेष प्रक्रिया को लेकर विवाद की स्थिति बन गई है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि पदोन्नति नियम 2025 फिलहाल न्यायिक परीक्षण के अधीन हैं और इन पर अंतरिम रोक लगी हुई है। ऐसे में पूर्व नियमों के आधार पर पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। कोर्ट ने 30 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के बाद शिक्षक संगठनों ने सरकार से मांग की है कि तय क्रम पहले पदोन्नति, फिर ट्रांसफर और अंत में अतिशेष का पालन किया जाए। जबलपुर हाईकोर्ट में दायर याचिका में 20 जून 2025 को जारी उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उच्च पदों पर कार्यवाहक नियुक्ति और प्रभार देने की प्रक्रिया को रोक दिया गया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम 2025 की वैधता अभी कोर्ट में विचाराधीन है और इस पर अंतरिम रोक भी लगी है। राज्य के वकील ने भी इस तथ्य की पुष्टि की। इसी आधार पर कोर्ट ने निर्देश दिया कि नए नियमों से प्रभावित हुए बिना, पूर्व प्रभावी प्रावधानों के तहत पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए और आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के 30 दिनों के भीतर इसे पूरा किया जाए।

प्रभार देने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उच्च पदों पर कार्यवाहक नियुक्ति और प्रभार देने की प्रक्रिया को बिना विलंब शुरू किया जाए। यह प्रक्रिया संशोधित नियमों से प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि उन पर फिलहाल रोक लगी हुई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इन पदोन्नतियों का अंतिम निर्णय याचिका के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। साथ ही राज्य सरकार को 30 दिनों के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के सदस्य उपेंद्र कौशल ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार सबसे पहले पदोन्नति और प्रभार की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। इसके बाद ही स्थानांतरण और अंत में अतिशेष की कार्रवाई की जानी चाहिए। मोर्चा का मानना है कि यदि इस क्रम का पालन नहीं किया गया, तो प्रदेश के हजारों शिक्षकों के हित प्रभावित होंगे और प्रशासनिक असंतुलन की स्थिति बन सकती है।

गलत क्रम से बढ़ सकता है विवाद

शिक्षक संगठनों का कहना है कि यदि पहले ट्रांसफर या अतिशेष की प्रक्रिया शुरू की जाती है, तो पदोन्नति के पात्र शिक्षकों को नुकसान होगा। इससे कई पदों पर असंतुलन पैदा होगा और बाद में सुधार करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्रशासनिक दृष्टि से भी पहले पदोन्नति, फिर ट्रांसफर और अंत में अतिशेष की प्रक्रिया अपनाना जरूरी है। संयुक्त मोर्चा ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि हाईकोर्ट के निर्देशों का पूर्ण पालन किया जाए और प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से लागू किया जाए। मोर्चा ने चेतावनी दी है कि यदि आदेश के अनुसार कार्रवाई नहीं की गई, तो शिक्षक संगठन आंदोलन का रास्ता भी अपना सकते हैं।

गर्मी का प्रकोप, सड़क पर तड़प-तड़प कर गिरे कबूतर

छिंदवाड़ा में आसमान से बरसती आग ने ली बेजुबानों की जान

छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जिले के परासिया में लगातार बढ़ते तापमान ने अब पशु-पक्षियों के लिए भी गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। रविवार दोपहर पेंचवेली स्कूल से भंडारिया जाने वाले मार्ग, वार्ड क्रमांक 17 में कई कबूतर मृत अवस्था में मिले, जबकि कुछ तड़पते हुए देखे गए। घटना के बाद क्षेत्र में चिंता का माहौल है और लोग इसे भीषण गर्मी का असर मान रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोपहर करीब साढ़े तीन बजे जब तापमान अपने चरम पर था, तब सड़क और आसपास का क्षेत्र अत्यधिक गर्म हो गया था। इसी दौरान कबूतर अचानक जमीन पर गिरने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने देखा कि कई कबूतर दम तोड़ चुके थे। भंडारिया में आयोजित एक विवाह समारोह में पहुंचे विनय राजा जोशी ने बताया कि सड़क किनारे झाड़ियों और खुले मैदान में बड़ी संख्या में कबूतर मृत पड़े थे, जिससे स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। क्षेत्र में इन दिनों तापमान

40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। सुबह से ही तेज धूप और दोपहर में चलने वाली गर्म लू लोगों के साथ-साथ जीव-जंतुओं के लिए भी खतरनाक साबित हो रही है। घरों के भीतर का तापमान भी 35-36 डिग्री तक पहुंच रहा है, जिससे राहत मिलना मुश्किल हो गया है। पशु-पक्षी प्रेमी जितेंद्र मौर्य के अनुसार, कबूतरों की मौत के पीछे मुख्य कारण पानी की कमी, अत्यधिक गर्मी और भोजन की अनुपलब्धता है। उन्होंने बताया कि कबूतर अपने शरीर का तापमान नियंत्रित रखने के लिए पानी पर निर्भर रहते हैं, लेकिन पानी न मिलने पर वे तेजी से कमजोर हो जाते हैं।

नागरिकों से छत पर पानी रखने की अपील- इसके अलावा गर्म तासीर वाले अनाज का सेवन भी उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि गंदगी और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर रहने से संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि कंक्रीट के बढ़ते जंगलों के कारण प्राकृतिक ठंडक खत्म हो रही है, जिससे पक्षियों को राहत नहीं मिल पाती। ऐसे में नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने घरों की छत या बालकनी में मिट्टी के बर्तनों में स्वच्छ पानी रखें और पक्षियों के लिए सुरक्षित स्थानों पर दाना डालें।

आदर्श और वर्ग चेतना के लिए प्रतिबद्ध कम्युनिस्ट थे होमी दाजी

भोपाल। अपने समय के दिग्गज कम्युनिस्ट नेता और पूर्व सांसद कॉमरेड होमी एफ दाजी की जन्म शताब्दी के अवसर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा स्थानीय हिन्दी भवन में समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रबुद्ध वक्ताओं ने कॉमरेड होमी एफ दाजी के कम्युनिस्ट आन्दोलन के लिए प्रेरक अवदान का उल्लेख करते हुए उन्हें एक आदर्श और प्रतिबद्ध कम्युनिस्ट निरूपित किया। समारोह के मुख्य अतिथि वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता और मार्क्सवादी चिंतक कॉमरेड अजित कुमार जैन ने 'राजनीतिक चेतना और समकालीन परिदृश्य' विषयक मुख्य वक्तव्य में कॉमरेड होमी एफ दाजी के प्रेरक अवदान और वर्ग चेतना के लिए प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए विभिन्न संस्मरणों के माध्यम से उनके राजनीतिक कौशल का उल्लेख किया। कॉमरेड जैन ने कहा कि 'श्रमिक आन्दोलन वर्ग संघर्ष नहीं है। कॉमरेड होमी दाजी मार्क्सवादी चेतना से लैस थे। उन्होंने वर्ग संघर्ष की सही समझ अर्जित की थी। इसलिए वे अपने परिदृश्य में श्रमिक आन्दोलन को इस हेतु प्रेरित कर सके। फासीवाद का वैचारिक मुकाबला मेहनतकशों की वर्ग चेतना से ही किया जा सकता है। कॉमरेड होमी दाजी की कार्य पद्धति और राजनीतिक कौशल इस हेतु प्रेरक और अविस्मरणीय है।'

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता कॉमरेड बादल सरोज ने कहा कि 'जनता की भाषा में जनता के हक की लड़ाई किस तरह लड़ी जाती है यह हमने कॉमरेड होमी दाजी से सीखा है । कॉमरेड होमी दाजी ने अपने आचरण से धर्म निरपेक्षता के महत्व को प्रतिपादित किया। यह उनकी महानता थी कि हम उनसे लड़ सकते थे और अपनी असहमति भी दर्ज कर सकते थे। मार्क्सवादी विचारधारा दुनिया की बेहतरी के लिए संघर्ष कर रहे साथियों की सबसे बड़ी ताकत है। इसे कॉमरेड होमी एफ दाजी ने साबित किया।'

एटक के प्रांतीय महासचिव कॉमरेड शिवशंकर मौर्य ने समकालीन परिदृश्य में श्रमिक आन्दोलन के समक्ष संकट और चुनौतियां का उल्लेख करते हुए कॉमरेड होमी दाजी के अवदान को श्रमिक आन्दोलन के लिए प्रेरणास्पद निरूपित किया। समारोह का संचालन व विषय प्रवर्तन करते हुए सत्यम पांडे ने होमी एफ दाजी के जीवन मूल्यों और प्रतिबद्धता को रेखांकित किया और प्रतिकूल स्थिति में भी कम्युनिस्ट आन्दोलन में अपने दायित्व निर्वहन के लिए सजग रहने के लिए उनके अवदान को अत्यंत महत्वपूर्ण निरूपित किया। समारोह की अध्यक्षता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मध्य प्रदेश राज्य सचिव कॉमरेड शैलेन्द्र शैली ने की। कॉमरेड शैलेन्द्र शैली ने कहा कि फासीवाद का प्रतिरोध सिर्फ कम्युनिस्ट ही कर सकते हैं। इसके लिए कम्युनिस्ट आन्दोलन को वैचारिक, राजनीतिक और सांगठनिक स्तर पर और अधिक मजबूत बनाना तथा हमारे प्रतिरोध को और अधिक प्रखर करना हमारा ऐतिहासिक दायित्व है।इस दायित्व के निर्वहन हेतु कॉमरेड होमी एफ दाजी का अवदान हमारा मार्गदर्शक है।' अन्त में भाकपा जिला भोपाल के सचिव कॉमरेड अजय राउत ने आभार व्यक्त किया।

श्योपुर में लावारिस बच्ची से खुला मानव तस्करी नेटवर्क

उद्योगपति दंपती समेत छह आरोपी गिरफ्तार ; पूछताछ जारी

श्योपुर। श्योपुर के सोंईकलां के पास हाईवे किनारे मिली दो साल की लावारिस बच्ची का मामला अब एक बड़े मानव तस्करी नेटवर्क तक जा पहुंचा है। जिला पुलिस ने 35 घंटे के ताबड़तोड़ ऑपरेशन में तीन जिलों से उद्योगपति दंपती समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे रैकेट से पर्दा उठाना शुरू कर दिया है। घटना की शुरुआत 18 अप्रैल को हुई, जब सोंईकलां के पास हाईवे किनारे एक मासूम बच्ची लावारिस हालत में मिली। पुलिस ने जब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक कार एमपी 07 जेडए 0067 की चाल संदिग्ध लगी। कार बेहद धीमी गति से चल रही थी। नंबर के आधार पर कार मालिक का पता लगाया गया जो राजगढ़ निवासी आकाश मूंदड़ा निकला। यहीं से जांच की सुई मानव तस्करी के बड़े नेटवर्क की ओर घूम गई। एसपी सुधीर अग्रवाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तीन विशेष टीमें गठित कीं। करीब 20 पुलिसकर्मियों ने 35 घंटे तक इंदौर, धार और खरगौन में दबिश दी। इस दौरान छह आरोपियों को दबोचा गया। गिरफ्तार आरोपियों में इंदौर के महालक्ष्मी नगर में ब्यूटी पार्लर संचालिका नीता जैन और उसका पति वैभव जैन शामिल हैं। वैभव जैन उद्योगपति बताया जा रहा है। इनके अलावा राजगढ़ के आकाश मूंदड़ा, उसकी पत्नी कृतिका मूंदड़ा तथा धार और खरगौन की दो महिलाएं भी गिरफ्तार हुई हैं।

रुह कंपा देने वाले हुए खुलासे

पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बच्ची का सौदा 21 नवंबर 2024 को किया गया था, जब वह महज छह दिन की थी। धार जिले की एक क्लीनिक संचालिका ने बच्ची को खरगोन की महिला से लेना बताया। इसके बाद इंदौर में नीता जैन और उसके पति वैभव जैन के जरिए यह मासूम राजगढ़ के आकाश मूंदड़ा को करीब एक लाख रुपये में बेच दी गई। इस तरह बच्ची कई हाथों से गुजरती रही और अंत में लावारिस हालत में हाईवे पर छोड़ दी गई। जांच में सबसे मजबूत कड़ी इंदौर के महालक्ष्मी नगर से जुड़ी मिली है। पुलिस को संकेत मिले हैं कि यहां ब्यूटी पार्लर की आड़ में पूरा नेटवर्क संचालित हो रहा था। बच्ची के खरीदार और सप्लायर दोनों यहीं से एक दूसरे के संपर्क में आए। पार्लर में आने वाली महिलाओं की आड़ में सौदेबाजी की जाती थी। पुलिस अब पार्लर के बैंक खातों और कॉल डिटेल खंगाल रही है। फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि मासूम के असली माता-पिता कौन हैं। धार और खरगौन की गिरफ्तार महिलाओं से पूछताछ जारी है। एसपी सुधीर अग्रवाल का कहना है कि बच्ची को जन्म देने वाली मां और पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने के लिए जांच तेज कर दी गई है। जल्द ही पूरे रैकेट का खुलासा किया जाएगा।

इंदौर, धार और खरगोन में पुलिस टीम की दबिश

श्योपुर पुलिस की तीन टीमों ने एक साथ इंदौर, धार और खरगोन में दबिश दी। आरोपियों को पकड़कर श्योपुर लाया गया है। पूछताछ में कई और नाम सामने आने की उम्मीद है। पुलिस को आशंका है कि यह गिरोह लंबे समय से नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त में लिप्त है। एक मासूम को सिर्फ छह दिन की उम्र में बेच देना और दो साल तक हाथों-हाथ बिकते रहना मानवता को शर्मसार करता है। श्योपुर पुलिस की तत्परता से इस घिनौने कारोबार का पर्दाफाश होना शुरू हुआ है। अब पूरे प्रदेश की नजर इस जांच पर टिकी है कि बच्ची के असली माता-पिता कौन हैं और इस नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं।

कूलर के सामने सोने को लेकर भाई-बहन में विवाद

नौंवी की छात्रा ने लगाई फांसी, कटिंग कराने गया था भाई

भोपाल। भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र स्थित चूनाभट्टी इलाके में कूलर के सामने सोने की मामूली बात पर हुए विवाद के बाद 14 वर्षीय छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार आशी चौधरी (14) निजी स्कूल में कक्षा नौवीं की छात्रा थी। उसके पिता का पहले ही निधन हो चुका है, जबकि मां 10 नंबर स्थित एक बुटीक पर काम करती है। घटना के समय घर में केवल आशी और उसका 18 वर्षीय भाई मौजूद थे। पुलिस के अनुसार रविवार शाम करीब 4 बजे दोनों भाई-बहन कूलर के सामने सो रहे थे।

इसी दौरान कूलर के पास सोने को लेकर दोनों के बीच हल्की कहासुनी हो गई। विवाद के बाद भाई बाल कटवाने के लिए घर से बाहर चला गया। करीब दो घंटे बाद जब वह लौटकर घर पहुंचा तो बहन को कमरे में फांसी के फंदे पर लटका पाया। घबराए भाई ने तुरंत आसपास के लोगों को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके का मुआयना करने के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। जांच के दौरान कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। एएसआई चंद्रभान सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि भाई-बहन के बीच कूलर के सामने सोने को लेकर सामान्य विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

इंदौर में महिला एसीपी के लापता पति राजस्थान में मिले

तलाश में जुटी थी पुलिस की कई टीमें,विवाद के बाद छोड़ा था घर

इंदौर। पीटीसी में रहने वाली एक महिला एसीपी के पति रविवार और सोमवार की दरमियानी रात अचानक लापता हो गए थे। इसके बाद महिला एसीपी ने आजाद नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने उनका लोकेशन ट्रैक किया है और राजस्थान के निंबाहेड़ा से बरामद किया है। बताया जा रहा है कि घर में हुए विवाद के बाद वे सरकारी जीप लेकर निकल गए थे। इसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। जानकारी के अनुसार रात में एसीपी और उनके पति के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। विवाद के बाद पति घर से सरकारी वाहन लेकर निकल गए। जाते समय उन्होंने ऐसी बातें कही थीं, जिससे किसी अनहोनी की आशंका जताई जा रही है। इसी कारण एसीपी ने देर किए बिना थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

राजस्थान में मिला आखिरी लोकेशन- शिकायत मिलते ही इंदौर के आजाद नगर थाना पुलिस हरकत में आ गई। मामले को संवेदनशील मानते हुए तुरंत टीम गठित की गई और तलाश शुरू कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक मोबाइल लोकेशन के आधार पर उनकी आखिरी लोकेशन राजस्थान के डग-बड़ौद क्षेत्र में मिली है। इसके बाद पुलिस की एक टीम वहां के लिए रवाना की गई है और आसपास के इलाकों में भी खोजबीन की जा रही थी। उन्हें निंबाहेड़ा से बरामद किया गया है। इंदौर पुलिस उन्हें राजस्थान से लेकर लौट रही है।

तलाश का बढ़ाया जा रहा दायरा- इतना ही नहीं एसीपी ने अपने सर्कल के दूसरे थाने से भी एक अलग टीम भेजी है ताकि तलाश का दायरा बढ़ाया जा सके। पुलिस लगातार तकनीकी माध्यमों से लोकेशन ट्रैक कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला एसीपी खुद भी इंदौर से डग-बड़ौद के लिए रवाना हो गई हैं। वे लगातार पुलिस टीमों के संपर्क में हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस पूरे मामले की जानकारी अभी तक वरिष्ठ अधिकारियों को औपचारिक रूप से नहीं दी गई है। अब मिलने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है।

50 फीसदी खराब चमक वाला गेहूं भी खरीदेगी मोहन सरकार

सीएम ने किसानों को दिया भरोसा, कहा-घबराएं नहीं अन्नदाता

भोपाल। मध्यप्रदेश में किसानों को बड़ी राहत मिली है। सीएम मोहन यादव ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। 50 फीसदी तक खराब चमक वाला गेहूं भी मोहन सरकार खरीदेगी। इतना ही नहीं प्रदेश सरकार ने पानी की कमी के कारण कम विकसित दाने की सीमा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत, क्षतिग्रस्त दानों की सीमा 6 प्रतिशत बढ़ा दी है। दरअसल, मोहन सरकार इस साल किसान कल्याण वर्ष मना रही है। सरकार लगातार किसानों के कल्याण के लिए फैसले ले रही है। सीएम की कोशिशों के बाद मध्य प्रदेस में गेहूं उपार्जन का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। साथ ही किसान गेहूं को बेचने के लिए नौ मई तक स्लॉट बुकिंग कर सकेंगे। पहले 30 अप्रैल तक थी।

किसानों के लिए एमपी में 3516 उपार्जन केंद्र चल रहे

वहीं, मध्य प्रदेश में किसानों के लिए 3516 उपार्जन केंद्र चल रहे हैं। उपार्जन केंद्रों की क्षमता 1000 क्विंटल से बढ़ाकर 2250 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। अभी तक मध्य प्रदेश में गेहूं बेचने के लिए कुल 8 लाख 55 हजार किसानों ने स्लॉट की बुकिंग करवाई है। वहीं, तीन लाख 96 हजार कृषकों से 16 लाख 60 हजार मीट्रिक टन गेहूं उपार्जित कर दो हजार 527 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसके साथ ही मध्यम-बड़े श्रेणी के 40 हजार 457 कृषकों द्वारा 5 लाख

88 हजार मीट्रिक टन मात्रा के स्लॉट बुक किए गए हैं। किसानों को तहसील के स्थान पर जिले के किसी भी उपार्जन केन्द्र पर उपज विक्रय की सुविधा दी गई है। अब खराब चमक वाले गेहूं को खरीदने की घोषणा मोहन सरकार ने कर दी है। इससे किसानों को बड़ी राहत मिली है।

चार गुना मुआवजा देने का भी किया है ऐलान

हाल ही में सीएम यादव ने किसानों की समृद्धि के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया। इस फैसले के मुताबिक, अब किसानों को उनकी भूमि के बदले 4 गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। यह निर्णय किसानों के अधिकारों की रक्षा करेगा और उनके भविष्य को सुरक्षित करेगा। राज्य सरकार ने दलहन, उड़द और तिलहन फसल, सरसों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उड़द को तय समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा और किसानों को तय समर्थन मूल्य के अतिरिक्त खरीदी गई उड़द पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस राशि भी दी जाएगी।

संपादकीय

ट्रंप पर दूसरा हमला

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर वाशिंगटन के होटल हिल्टन में डिनर पार्टी के दौरान हुए जानलेवा हमले से जहां अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं यह ट्रंप की अपने ही देश में बढ़ती अलोकप्रियता का भी यह स्पष्ट संकेत है। हमलावर अमेरिकी है और वो ट्रंप को गद्दार बता रहा था। हालांकि अमेरिकी सीक्रेट एजेंटों ने तत्काल जवाबी कार्रवाई करते हुए हमलावर को दबोच लिया, लेकिन असल सवाल यही है कि इस अति उच्च स्तर की डिनर पार्टी में हमलावर हथियार लेकर पहुंचा कैसे? सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक क्यों नहीं लग पाई। जांच एजेंसियां इस हमले के पीछे ईरान कनेक्शन भी ढूंढ रही है, लेकिन प्राथमिक जांच में इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। गौरतलब है कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में शनिवार रात एक बार फिर हमले की कोशिश हुई। हालांकि हमलावर सीधे ट्रंप तक नहीं पहुंच पाया और घटनास्थल में घुसने के बाद ही राष्ट्रपति की सुरक्षा में जुटे सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने उसे मुठभेड़ के बाद जिंदा पकड़ लिया। हमलावर का नाम कोल टॉमस एलन बताया गया है, जो कि कैलिफोर्निया में एक शिक्षक रह चुका है। शुरूआती जांच में खुलासा हुआ है कि हमलावर ने इसकी लंबी प्लानिंग की थी। वह खुद भी होटल में बतौर अतिथि रूका हुआ था। इसलिए सुरक्षा एजेंसियों को उस पर शक नहीं हुआ और वह सुरक्षा घेरे को भेदकर पार्टी में पहुंच सका। हमलावर के हाथ में शॉटगन, हैंडगन और कई चाकू थे। खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने घटना के बाद बताया कि हमलावर कमरे (बॉलरूम) से लगभग 50 गज की दूरी पर था, जब उसने सुरक्षा चेकपॉइंट की ओर तेजी से दौड़ लगाई थी। बॉल रूम में पहुंचने के बाद उसने ताबड़तोड़ गोलियां दागीं, जिससे कई लोगों ने टेबलों के नीचे छिपकर अपनी जान बचाई। अमेरिकी कानून के मुताबिक हमलावर को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। इस हमले के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ-साथ दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इस हमले में राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के सकुशल बचने पर राहत जताई है। हालांकि जितनी जल्दी ट्रंप के सकुशल बचने पर भारत की सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आई, वैसी ईरानी सुप्रीमो अयातुल्लाह खामेनेई और उनके साथियों की अमेरिका द्वारा हत्या के मामले में नहीं दिखाई दी। अगर हमलावर का कोई ईरानी कनेक्शन नहीं है तो यह माना जाएगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रप की लोकप्रियता अपने ही देश में अब निचले स्तर पर है। ईरान युद्ध में उनकी कूटनीतिक और सैनिक विफलता उजागर हो चुकी है। उनके बड़बोलेपन और अस्थिर मनोवृत्ति का खमियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है। बावजूद इस सचाई के किसी भी राजनेता पर हिंसक हमला कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। वैसे भी बीते दो साल में ट्रंप पर यह दूसरा जानलेवा हमला है। दोनों में वो बच गए, यह भाग्य की बात है, लेकिन इससे उनके व्यवहार और कार्यशैली में किसी तरह की गंभीरता और विश्वसनीयता आई हो, यह कहीं से नहीं लगता। ईरान युद्ध और समूचे विश्व को ऊर्जा संकट में धकेलना ट्रंप की अदूरदर्शी नीतियों का ही परिणाम है। अगर उन्होंने युद्ध के बजाए कूटनीति से ही काम लिया होता तो दुनिया इतनी परेशान नहीं होती। ट्रंप यह भूल जाते हैं कि ईरान संकट की वजह से बाकी दुनिया के साथ साथ खुद अमेरिकी भी बहुत परेशान हैं। भारतीयों के प्रति उनके मन में विद्वेष के चलते कई प्रतिभाशाली भारतीय अब अमेरिका छोड़ने का मन बना रहे हैं। उधर ईरान ने जिस तरह ट्रंप को अपनी कूटनीति के जाल में फंसा दिया है, उससे निकलने का रास्ता भी ट्रंप को नहीं सूझ रहा है। हालांकि वो अब विक्टिम कार्ड खेलेंगे, यह तय है।

नजरिया

अवधेश कुमार

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

रिकॉर्ड मतदान किसके लिए फायदेमंद

भारतीय चुनाव में जो कभी नहीं हुआ वह 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हो गया। अभी तक 92.86 प्रतिशत मतदान रिकॉर्ड हुआ है। तमिलनाडु का भी लगभग 85 प्रतिशत मतदान एक रिकॉर्ड है। अंतिम आंकड़ा आने के बाद इसमें और वृद्धि होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में मतदान प्रतिशत औसत से अधिक रहा है किंतु वहां भी केवल 2018 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में 91.4% मतदान हुआ था। बंगाल में 2011 से मतदान औसत से ज्यादा रहा। 2011 में 84.5%, 2016 में 82.56% और 2021 में 81.56% मतदान हुआ। वैसे 2010 के बाद से मतदान में वृद्धि देशव्यापी प्रवृत्ति रही है। मतदान अंकगणित का विषय है लेकिन इसकी परिणति राजनीतिक होती है और उनके मायने राजनीति के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम तक जाते हैं। बंगाल का दूसरा चरण अभी बाकी है इसलिए संपूर्ण मूल्यांकन उसके बाद ही होगा। पर चुनाव के दौरान बने हुए माहौल का संकेत यही है की मतदान की रिकॉर्ड प्रवृत्ति में ज्यादा अंतर नहीं आने वाला और यहीं संकेत भी छिपा हुआ है। 2010 के पहले सामान्य मतदान में वृद्धि को सत्तारूढ़ पार्टी या घटकों की पराजय के रूप में देखा जाता था और अधिकतर मामलों में ऐसा ही हुआ। बाद में यह प्रवृत्ति बदल गई। मतदान बढ़ाने के बावजूद सरकारें वापस आती रही और मतदान घटना पर भी कई सरकारें गईं। इसलिए सामान्यतः मतदान का प्रतिशत किसी सरकार के जाने या नई सरकार के आने या इसके विपरीत राजनीति परिणाम का निश्चयात्मक संकेत नहीं माना जा सकता।

बंगाल में 2011 में 84.5 प्रतिशत का रिकार्ड मतदान हुआ और वामपंथी मोर्चे की 34 वर्षों की स्थापित सरकार चली गई। उसके बाद मतदान प्रतिशत थोड़ा-थोड़ा घटा किंतु ममता वापस आती रहीं। चुनाव आयोग द्वारा विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान या एसआईआर की प्रक्रिया के कारण अब वास्तविक मतदाताओं के नाम ही बचे हैं इसलिए हर राज्य में मतदान प्रतिशत संतोषजनक होगा। पिछले वर्ष बिहार के चुनाव में 67.25% मतदान हुआ जो 2020 के 57.29 प्रतिशत से 9.96% ज्यादा था। बिहार में लगभग 65 लाख नाम एसआईआर की प्रक्रिया में हटाए गए थे। बंगाल में कुल 90 लाख 83 हजार 345 मतदाताओं का नाम सूची से हटा। कई लाख मतदाताओं ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई हुई है और न्यायिक प्राधिकरणों को फैसला करना है। किंतु 7.66 करोड़ की जगह मतदाताओं की संख्या 6.7 करोड़ रह गई। यह सच नहीं है कि प्रतिशत ज्यादा होते हुए भी कुल मतों की संख्या इतनी नहीं बढी। पिछले चुनाव से लगभग 26 लाख ज्यादा मतदाताओं ने मतदान किया। भारी संख्या में मृतक, दूसरे जगह चले गए या दो जगह नाम वाले या कुछ फर्जी नाम मतदाता सूची में थे और उनके नाम मतदान होते थे जिनकी संख्या बहुत बड़ी थी। इनके नाम पर कितने वोट डाले गए इसकी गणना कोई नहीं कर सकता। अगर 6.77 करोड़ मतदाताओं के आधार पर पिछला मतदान होता तो मतदाताओं की संख्या कम होती और इस बार वृद्धि बहुत ज्यादा होती। इस महत्वपूर्ण पहलू की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।

2011 में ममता बनर्जी ने लगभग 5 वर्षों के अनवरत संघर्ष और आक्रामकता से मतदाताओं में वाममोर्चा सरकार के विरुद्ध गुस्सा एवं आलोड़न पैदा किया था। वाम मोर्चा समर्थक भी उनके साथ आये और तृणमूल का अपना भी आधार खड़ा हुआ। जब से भाजपा ने बंगाल में अपनी विचारधारा और राजनीति को जमीन पर उतारने का अभियान चलाया ममता के विरुद्ध समाज के निचले स्तरों पर जबरदस्त आलोड़न है और कुछ महीनो में 2011 पूर्व की स्थिति ममता एवं भाजपा के संदर्भ में उल्टी है। ममता समर्थक और विरोधी तथा भाजपा समर्थक और विरोधी दोनों पक्षों में स्वयं और अपने मतदाताओं को ज्यादा संख्या में मतदान केन्द्रों तक पहुंचाने की प्रबल भावना है। 2019 लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम दिखा जब भाजपा ने 40% मत के साथ राज्य 18 सीटें जीत ली। 2018 पंचायत चुनाव में भी जबरदस्त आलोड़न था और संकेत मिल गया कि भाजपा जमीन पर नीचे तक पहुंची है तथा राज्य से कांग्रेस और वाम दलों का लगभग सफाया हो चुका है। भाजपा और उसके विरोधियों की दो ध्रुवीय राजनीति में पक्ष और विपक्ष दोनों तरह की लहर भारत में देखा गया है। 2021 में भी भाजपा ने वातावरण बनाने की कोशिश की पर तब तीन सीटों से बहुमत के 148 तक पहुंचना बंगाल के सामाजिक - सांप्रदायिक समीकरणों में कठिन था। इसलिए लगभग 38% मत के साथ हुआ 77 सीटों तक पहुंच पाये। कोरोना महामारी के कारण बनाए गए सरकार विरोधी माहौल का भी थोड़ा असर हुआ। बंगाल में 1967 के बाद से ही मतदाताओं की सुरक्षा आम लोगों के लिए हमेशा बड़ा मुद्दा रहा है। चुनावी रैगिंग या धांधली प्रदेश का स्वाभाविक चरित्र पिछले 60 सालों में बना रहा है। कांग्रेस फिर वाम दल और तृणमूल कांग्रेस ने भी इस प्रवृत्ति को ज्यादा निष्ठुरता से कायम रखा।

इस बार मतदाताओं का बड़ी संख्या में निकलने का एक प्रमुख कारण मतदान और बाद में के लिए दिखता सुरक्षा आश्वासन था। पहले चरण के लिए केंद्रीय बलों की 2407 कंपनी, 2193 क्विक रिस्पांस टीम व 40,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। जहां कुछ कुछ समस्या हो रही थी मतदान के पहले से ही केंद्रीय बल तुरंत पहुंचते थे। मतदान के दौरान जहां भी समस्या आई सुरक्षा बल ज्यादातर पहुंचे। इसके बावजूद दक्षिण दिनाजपुर के एक भाजपा उम्मीदवार को लोगों द्वारा खदेड़ने और पकड़ कर पिटाई करते वीडियो देखने से अनुमान लग जाता है कि मतदान कैसे भय और आतंक के वातावरण में होता रहा। सुरक्षा व्यवस्था के कारण ही हिंसा में भी रिकॉर्ड कमी आई। मतदान बाद निश्चित समय तक केंद्रीय बलों की उपस्थिति के निर्णय ने भी मतदाताओं में सुरक्षा भाव पैदा किया। 2021 उसके पहले 2019 और 2018 तीनों चुनावों में मतदान बाद की हिंसा और लोगों के पलायन से भय का माहौल बना था। चुनाव अभियान के बीच प्रदेश की यात्रा करने वालों को 2026 में माहौल में बदलाव दिख रहा था। मतदाता धीरे -धीरे खुलकर अपना मत प्रकट करने लगे थे। लंबे समय बाद मतदान हत्याविहीन, न्यूनतम हिंसा और निर्भयता के वातावरण में संपन्न हुआ है। निस्संदेह, परिणाम में भी यह दिखाई देगा।

ममता और समर्थकों की आक्रामकता का जवाब भाजपा ने भी प्रति आक्रामकता से दिया। गृह मंत्री अमित शाह तक के भाषणों में भी आक्रामकता थी ताकि उनके समर्थक मतदाता भयरहित होकर मतदान के लिए निकलें और आक्रमण होतो उसका प्रतिकार करें या सुरक्षा बलों तक सूचना पहुंचाएं। ममता ने अपनी शैली में हमलावर प्रचार किया और यहां तक कहा कि किसी कार्यकर्ता के साथ कार्रवाई होगी तो सरकार उसके साथ खड़ी ही नहीं रहेगी बल्कि कुछ संस्थाओं के मामले में यहां तक कहा कि उसको हम सरकारी नौकरी दे देंगे। पहले भी ममता उन सबकी रक्षा में सामने दिखीं जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार या अपराध के मामलों में केंद्रीय एजेंसियों ने कार्रवाई की। इसका असर उनके घोर समर्थकों पर था। देश भर में आम मुसलमान भाजपा के विरुद्ध मतदान करता है और उनकी संख्या कहीं कहीं शत-प्रतिशत तक चली जाती है। बंगाल में उनकी आबादी 29 से 30 प्रतिशत के बीच होगी। वे भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए मतदान करने निकले ही होंगे। उसकी प्रतिक्रिया में गैर मुस्लिम समुदाय भी निकले हैं जो टीवी कैमरों पर दिख रहे थे। मुर्शिदाबाद , मालदा, दक्षिण दिनाजपुर आदि जिलों में निकले मतदाता गवाही दे रहे थे कि दोनों पक्षों में करो या मरो का भाव पैदा हो चुका है। जिलों के हिसाब से देखें तो दक्षिण दिनाजपुर में 95.4% , मालदा में 94.43%, मुर्शिदाबाद में 93.58%, उत्तर दिनाजपुर में 94.15%, अलीपुरद्वार में 92.69% , झारग्राम में 92.5%, पश्चिम मेदिनीपुर में 92.118% , बांकुरा में 92.5 0%, पूर्वी मेदिनीपुर में 91.20 प्रतिशत, तथा कूच बिहार में सबसे अधिक 96% मतदान हुआ है। इस दौर में सबसे कम कालिमपोंग में 83.07 प्रतिशत , दार्जिलिंग में 88.80 प्रतिशत, पश्चिम वर्धमान में 90.33% तथा पुरुलिया में 90.91% मतदान हुआ। साफ है कि जहां एक पक्ष कम रहा वहां मतदान प्रतिशत कम हुआ और दार्जिलिंग, कालिमपोंग आदि इसके उदाहरण हैं।

बंगाल को समझने वाले स्वीकार करेंगे कि तीन लगातार कार्यकाल के बाद ममता बनर्जी के विरुद्ध सत्ता विरोधी रुझान का भी वोट है तथा बदलाव के लिए निकलने वाले मतदाताओं के भी संख्या है। यह बताने की आवश्यकता नहीं की इन मतदाताओं ने किसके चुनाव चिन्ह पर बटन दबाया होगा। ममता और तृणमूल के राज में सत्ता से जुड़े निहित स्वार्थी तत्व तथा विरोधियों के विरुद्ध सत्ता व प्रशासन के भयानक दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, अपराध खासकर संदेशखाली व आरजी कर जैसी महिलाओं के विरुद्ध जघन्य अपराध घटनाएं भी सामने है, दंगों के दौरान प्रशासन की भूमिका, एक समय का संपन्न और उद्योगों तथा कारोबार के मामले में देश के अगुआ राज्य का पीछे होना और संपूर्ण आर्थिक स्थिति पर इसके नकारात्मक असर के कारण भी असंतोष दिखाई दे रहा है। भाजपा ने इन सबको मुद्दा बनाया। इस तरह रिकॉर्ड मतदान के पीछे इन समस्त कारकों की सामूहिक भूमिका रही।

वैसे इन 152 सीटों का पिछला अंकगणित देखें तो तृणमूल ने 92 में से 83 पर सीधे भाजपा, पांच पर कांग्रेस और तीन पर माकपा तथा एक पर भाजपा की सहयोगी और झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आशु को हराया था। इनमें से तीन दांतन,तमलुक और जलपाईगुडी में जीत का अंतर एक हजार से कम और नौ पर एक से पांच हजार का था। कुल मिलाकर इनमें से 23 पर जीत का अंतर 10 हजार से कम था। इनसे ज्यादा एसआईआर में नाम कट गये। एसएआर में औसत प्रतिशत 28, 055 नाम हटे हैं । इस तरह मतदान में वृद्धि का चुनाव परिणाम के संदर्भ में पूर्व आकलन किया जा सकता है।

किसान स्वायत्तता, जैव विविधता व पोषण की दिशा में एक राह

ओपन सोर्स बीज प्रणाली

निलेश देसाई

लेखक कृषि मामलों के जानकार हैं।

अंतरराष्ट्रीय बीज दिवस के अवसर पर मैंने ओपन सोर्स बीज प्रणाली की आवश्यकता महसूस की। आखिर यह ओपन सोर्स बीज प्रणाली है क्या? यह कहाँ काम करती है? इसकी जरूरत क्यों महसूस की जा रही है? क्या यह किसान की स्वायत्तता, जैव विविधता और पोषण सुरक्षा के लिए उपयोगी हो सकती है? और भारत में इसे नीतिगत रूप से लागू करने में क्या दिक्कतें हैं?

ओपन सोर्स बीज प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बीज किसी निजी कंपनी या बौद्धिक संपदा एकाधिकार के अधीन नहीं होता। इसका मूल विचार यह है कि बीज, उसकी जानकारी और उसका उपयोग किसानों, शोधकर्ताओं और समुदायों के लिए खुला रहे। यह सोच उस पुरानी किसान-परंपरा से जुड़ती है जिसमें बीज बचाना, साझा करना, बदलना और स्थानीय परिस्थिति के अनुसार सुधारना खेती का स्वाभाविक हिस्सा रहा है।

इस प्रणाली को सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं: जैसे मुक्त सॉफ्टवेयर (ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर) में कोई भी व्यक्ति कोड का उपयोग, सुधार और साझा कर सकता है, वैसे ही ओपन सोर्स बीज में किसान बीज को बचा सकता है, बो सकता है, बाँट सकता है और बेहतर भी बना सकता है। इसके पीछे 'बीज पर साझा अधिकार' की सोच है, न कि 'बीज पर निजी कब्ज़ा'।

यह कहाँ काम करती है?

ओपन सोर्स बीज आंदोलन की जड़ें अंतरराष्ट्रीय अनुभवों में मिलती हैं। भारत में भी इसे किसान-आधारित बीज संरक्षण, सामुदायिक बीज बैंक, सहभागी प्रजनन और खुले ज्ञान-साझाकरण से जोड़ा जाता है। यह प्रणाली विशेष रूप से वहाँ उपयोगी है जहाँ किसान स्थानीय जलवायु, मिट्टी, सूखा, वर्षा या पोषण जरूरतों के अनुसार बीजों को विकसित करना चाहते हैं। चावल, बाजरा, ज्वार, दालें और सब्जियों की कई पारंपरिक किस्में इस मॉडल के लिए उपयुक्त मानी जा सकती हैं, क्योंकि इनमें स्थानीय अनुकूलन की बड़ी क्षमता होती है।

इसकी आवश्यकता क्यों है?

भारत की खेती आज कई दबावों के बीच है–महँगे इनपुट, घटती मिट्टी-स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, बीज पर बढ़ती निर्भरता और बाजार का एकाधिकार। इस स्थिति में ओपन सोर्स बीज प्रणाली किसान को फिर से केंद्र में लाने की कोशिश करती है। यह केवल तकनीकी विकल्प नहीं, बल्कि कृषि-स्वायत्तता का प्रश्न है। जब बीज किसान के पास रहता है, तो वह हर मौसम में बाजार का खरीदार नहीं बनता। वह अपने अनुभव, अपनी मिट्टी और अपनी जलवायु के अनुसार बीज चुन सकता है।

किसान की स्वायत्तता, जैव विविधता और पोषण

स्वायत्तता: किसान केवल उपभोक्ता नहीं रहता, वह सह-नवप्रवर्तक बनता है। उसे हर साल बीज खरीदने की मजबूरी नहीं होती।

जैव विविधता: स्थानीय बीजों में जलवायु संकट (सूखा, बाढ़) झेलने की क्षमता अधिक होती है। ओपन सोर्स मॉडल इन किस्मों को खेतों में जीवित रखता है।

पोषण: पारंपरिक फसलें जैसे रागी, कोदो, कुटकी और देसी दालें पोषण से भरपूर होती हैं। ओपन सोर्स प्रणाली इन 'सुपरफूड्स' के बीजों तक सबकी पहुँच सुनिश्चित करती है।

भारत में नीतिगत दिक्कतें और कानूनी पक्ष

भारत में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कानून और आगामी नीतियां (जैसे प्रस्तावित बीज विधेयक) बीज को मुख्यतः एक वाणिज्यिक वस्तु के रूप में देखती हैं। जहाँ सरकार नकली बीजों पर रोक और गुणवत्ता नियंत्रण चाहती है, वहीं डर यह है कि कहीं सामुदायिक बीज विनिमय पर भी व्यावसायिक कड़ाई न लागू हो जाए। एक दूसरी विसंगति यह है कि ओपन सोर्स बीज प्रणाली को अभी स्पष्ट कानूनी मान्यता नहीं मिली है। किसान अपने बीज बचा तो सकता है, लेकिन यदि किसी स्थानीय किस्म पर किसी कंपनी या संस्थान का नियंत्रण बढ़ जाए, तो किसान का अधिकार कमजोर पड़ सकता है। इसलिए नीति-निर्माण में किसान की छूट, सामुदायिक संरक्षण और गैर-व्यावसायिक बीज विनिमय को साफ़ कानूनी सुरक्षा देनी होगी।

हालाँकि, भारत के पास एक मजबूत कानूनी आधार पहले से मौजूद है– पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001।

समाधान के लिए हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना होगा:

1. पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम की मजबूती: इस कानून की धारा 39 स्पष्ट रूप से किसान को अपने खेत की उपज से बीज बचाने, उपयोग करने, बोने, विनिमय करने या साझा करने का अधिकार देती है, भले ही वह किस्म संरक्षित ही क्यों न हो। ओपन सोर्स बीज प्रणाली को इसी कानून के दायरे में और अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

2. कानूनी स्पष्टता: यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसान-से-किसान बीज साझा करना किसी भी स्थिति में अपराध न माना जाए। घरेलू बीज बैंक और सामुदायिक बीज पंचायतों को व्यावसायिक बिक्री से अलग श्रेणी में रखा जाए।

3. सार्वजनिक अनुसंधान: सार्वजनिक संस्थानों और किसान समूहों को मिलकर ऐसी किस्में विकसित करनी चाहिए जो 'पैटेंट' मुक्त हों और जिनका लाभ सभी को मिले।

4. संतुलित पंजीकरण: बीज का पंजीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण बाजार के लिए कड़ा हो, लेकिन ग्रामीण स्तर की परंपरागत विनिमय प्रणाली को बाधित न किया जाए।

ओपन सोर्स बीज प्रणाली कोई भावनात्मक नारा नहीं, बल्कि बीज, भोजन और किसान की स्वतंत्रता से जुड़ा एक व्यावहारिक मॉडल है। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 द्वारा दिए गए कृषक अधिकारों को आधार बनाकर हम एक ऐसी व्यवस्था खड़ी कर सकते हैं जहाँ बीज पर किसी कंपनी का एकाधिकार न होकर पूरे समुदाय का साझा अधिकार हो।

अगर भारत सचमुच 'किसान प्रथम' की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे बीज को केवल एक उत्पाद नहीं, बल्कि 'कृषि-स्वराज' का आधार मानना होगा।

महिला भागीदारी के बिना 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का सपना अधूरा

मातृशक्ति वंदन अधिनियम

सीए अखिलेश जैन

लेखक भाजपा मध्यप्रदेश के प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं।

भारत लोकतंत्र की जननी है, भारत को मदर ऑफ डिमोक्रेसी कहा जाता है और भारत की आजादी के स्वर्णिम काल में भारत एक अति महत्वपूर्ण, अत्यावश्यक व दूरदृष्टि से भरा निर्णय होते -होते रह गया, यह निर्णय केवल राजनीतिक निर्णय भर नहीं था। मातृशक्ति वंदन अधिनियम को लागू करना केवल राजनैतिक निर्णय कहना निर्णय के साथ नाइंसाफी है। इस निर्णय के दूरगामी परिणामों का विश्लेषण करना अत्यावश्यक है।

महिलाएँ पंचायत से लेकर स्थानीय निकायों का नेतृत्व काफी समय से कर रही हैं। अगर महिलाओं को संसद व विधानसभाओं में आरक्षण का लाभ मिल जाता है, तो तमाम राजनैतिक दलों को महिलाओं की उन्नति का नारा देकर काम निकालने की जगह वास्तव में महिला प्रतिनिधियों को संसद व विधानसभाओं के लिए अवसर प्रदान करना पड़ता और धीरे -धीरे महिला नेतृत्व समय के साथ परिपक्वता को प्राप्त कर लेता।

जिस देश को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, उसी देश में 50 प्रतिशत आबादी को नीति - निर्णय में भागीदारी से दूर रखने का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास हुआ है, लोकतंत्र की दुहाई देने वालों ने लोकतंत्र की जड़ों को सींचने की जगह, लोकतंत्र की जड़ों पर मठठा डाल दिया, वो भी केवत निहित स्वार्थों के चलते।

भारत की आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक प्रगति का आधार भारत का लोकतंत्र है। लोकतंत्र व संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को समान नागरिक अधिकार प्रदान किये हैं। देश आज उस मोड़ पर आकर खड़ा है जहाँ से विकसित भारत@2047, 5 ट्रिलियन डॉलर कि अर्थव्यवस्था का सपना संजोये हुआ है। आजादी के 78 वर्षों के बाद भी महिलाओं का योगदान विनिर्माण क्षेत्र में 27 प्रतिशत तक ही पहुँच पाया है। वो भी मोदी सरकार के तमाम प्रयासों के बाद, अगर भारत को विकसित भारत@ 2047 तथा 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित समय सीमा में हासिल करना है तो देश की 50 प्रतिशत आबादी को घरों से बाहर निकाल कर देश निर्माण में भागीदार बनाना ही पड़ेगा।

महिलाओं की नीति - निर्णय में हिस्सेदारी निश्चित रूप से सरकार की नीति - निर्णयों को प्रभावित करती, महिलाओं के पक्ष को मजबूती मिलती, 50 प्रतिशत आबादी का योगदान सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता, महिला सुरक्षा और मजबूत होती, महिलाओं को तमाम नए अवसर मिलते, विशिष्ट परिवारों की महिलाओं का वर्चस्व टूटता, सामान्य परिवारों और छोटी - छोटी जगह की महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक निर्णयों में भागादारी होती, वास्तव में सम्पूर्ण देश की महिलाओं का वास्तविक प्रतिनिधित्व होता, निश्चित रूप से प्रगति का पहिया अपने आप तीव्र गति से दौड़ता। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने में आने वाली रुकावटें जब तक जारी रहेंगी, नीति - निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी का पक्ष जब तक जनसामान्य की महिलाओं तक पहुँच कर मजबूत व स्थाई नहीं होता, तब तक विकसित भारत@ 2047 व 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य भारत में कठिनाईयों से भरा रहेगा, महिलाओं की नीति - निर्णयों में भागीदारी के बिना अगर एक बार विकसित भारत@ 2047 व 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य किसी तरह हासिल भी कर लिया जाता है तो उसके स्थायित्व पर शंका सदैव बनी रहेगी।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

राजेंद्र बज

लेखक व्यंग्यकार हैं।

सत्ता के सुरूर की मगरूरियत

सत्ता के सुरूर में आदमी को अपने कद और पद की तुलना में यह जमीन संकरी और आसमान छोटा नजर आता है। वह इस दुनिया में रहकर भी इस दुनिया में नहीं होता। उसका हाव भाव और व्यवहार इस दुनिया में ऐसा होता है जैसे कि वह इस दुनिया पर उपकार कर रहा हो। वैसे यह तो तय है कि जिस किसी शख्सियत को सत्ता मिल जाती है या सत्ता से निकटता हांसिल हो जाती है, उसने पूर्व भव में महान पुण्य कर्म किए होंगे। अन्यथा आजकल के जमाने में हाथ फैला कर चाहे लाख ऊपर वाले की दुहाई दी जाएं, अपना और अपनों का पेट भरना कोई आसान नहीं है।

लोकतंत्र में व्यक्तिगत रूप से हर किसी सत्तासीन का पत्ता कटने की प्रबल संभावना भी हुआ करती है। यह स्थिति राजनीतिक समीकरण के साथ-साथ जर्जर होती काया के चलते भी बन सकती है। लेकिन वैचारिक दमखम की दृष्टि से आत्मनिर्भर शख्सियत मरणासन्न अवस्था में भी सत्ता की ऊर्जा से परिपूर्ण रहने का लोभ संवरण नहीं कर पाती। दरअसल हर छोटी-बड़ी सत्ता में यह चमत्कारिक गुण होता है कि इसके चलते आदमी के अंतर्मन में असीम ऊर्जा एवं चेतना का प्रबल संचार होने लगता है। एक प्रकार से सत्ता हाथ आते ही हौसलों को पर लग जाते हैं। आदमी मानसिक दृष्टि से भरपूर यौवन को प्राप्त कर लेता है। यही कारण है कि सत्ता के सुरूर की मगरूरियत दिल और दिमाग पर छा जाती है।

एक प्रकार से जब राजयोग उदय में आता है तब सत्ता प्राप्ति के योग बना करते हैं। वैसे सत्तासीन परिवार में जन्म लेना भी राजयोग का लक्षण है। इसके अतिरिक्त सत्ताधारी परिवार से नाते रिश्तेदारी होना या नए रिश्ते का सृजन होना भी महान पुण्य कर्म के उदय का प्रतीक माना जा सकता है। आजकल के दौर में ब्याह शादी के मामले में प्रस्तावित वर वधू के 'कुंडली मिलान' की प्रक्रिया के पैमाने बदलते जा रहे हैं। अब इसमें पद और पैकेज के साथ-साथ लोकतांत्रिक राजघराने से राजघराने के स्तर तक का संज्ञान लिया जाने लगा है। नेता, नेता के घर से बेटी लें, नेता, नेता के घर में बेटी दें - तो एक और एक ग्यारह का गणित राजनीति में जड़ जमाने में बहुत काम का होता है।

दरअसल सत्ता के मद का सुरूर केवल और केवल सत्ता पाने वाले को ही नहीं होता अपितु न केवल उनके परिजन, रिश्तेदार, परिचित बल्कि उनके पक्ष में 'जिंदाबाद-मुर्दाबाद' करते रहने वालों को भी होता है। दरअसल सत्ता अपने आप में परम सत्ता होती है। इसके आगे सब बौने नजर आते है। सत्ता मिलने पर कुछ भी करो, बोलो, चीखो चिल्लाओ, प्रत्युत्तर में केवल और केवल - जी सर, जी सर, जी सर, का ही उद्घोष सुनाई देता है। वास्तव में सत्ता के सुरूर की मगरूरियत का तो यह आलम है कि बस चले तो स्वर्ग के सिंहासन पर भी नजरें इनायत कर ली जाएं। अब यह तो पता नहीं कि स्वर्ग में लोकतंत्र जैसी कोई शासन व्यवस्था है या नहीं ? यदि है तो, क्या पता हमारा लोकतंत्र वहां लागू हो जाएं !

इतना जरूर है कि चाहे हमारे यहां सत्ता का सुरूर आदमी को मगरूर कर देता हो, लेकिन इस बात की तो दूर-दूर तक नहीं कोई संभावना नहीं है कि कोई ठस बुद्धि का परिचय दे सकें। वरना इतिहास साक्षी है कि हमारे यहां एक दिन की सत्ता में चमड़े के सिक्कों का चलन लागू कर दिया गया था। जबकि हमारे यहां तो 5 वर्ष का प्रावधान है। वैसे इस संदर्भ में यह मानना होगा कि हमारे यहां सत्ता के मद में मगरूरियत चाहे देखने में आती हो, लेकिन इतिहास की पुनरावृति की कोई संभावना नहीं है। हमारे यहां तो पद पर रहते तो राजा, राजा होता ही है, लेकिन पद जाने के बाद भी 'भूतपूर्व राजा' का खिताब तो मरते दम तक साथ देता है। वैसे थोड़ी कम ही सही लेकिन इसमें भी एक अलग प्रकार की मगरूरियत है।

बलिदान दिवस पर विशेष

धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), संस्कृति, पर्यटन
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

राजा हिरदेशाह लोधी: बुन्देला विद्रोह के विस्मृत महानायक

मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के हीरापुर रियासत में जन्मे राजा हिरदेशाह लोधी एक ऐसी परंपरा के वाहक थे, जहाँ मातृभूमि की रक्षा को ही परम धर्म माना जाता था। वह केवल एक भूमिपति या जागीरदार नहीं थे, बल्कि अपनी प्रजा के सुख-दुख के साथी थे। 19वीं सदी के चौथे दशक तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी दमनकारी नीतियों और कुत्सित 'डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स' के माध्यम से भारतीय रियासतों को निगलना शुरू कर दिया था। जब अंग्रेजों की गिद्ध दृष्टि नरसिंहपुर और सागर क्षेत्र की उपजाऊ भूमि पर पड़ी, तब हिरदेशाह लोधी ने गुलामी को स्वीकार नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों के विरूद्ध अपनी तलवार उठा ली।

भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास को हम जब भी पलटकर देखते हैं, तो अक्सर 1857 की क्रांति को ही विद्रोह का प्रारंभिक बिंदु मान लिया जाता है। लेकिन अगर इतिहास की गहराइयों में झांकें तो पता चलता है, कि मंगल पांडे के विद्रोह से भी 15 वर्ष पूर्व, मध्य भारत की विंध्य पर्वतमालाओं और नर्मदा के कछारों में औपनिवेशिक शासन के विरूद्ध क्रांति प्रारंभ हो चुकी थी। 1842 का बुन्देला विद्रोह इस प्रतिरोध का प्रारंभिक उदाहरण है। इस क्रांति को प्रारंभ करने वाले महानायक थे- हीरापुर के राजा हिरदेशाह लोधी।

मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के हीरापुर रियासत में जन्मे राजा हिरदेशाह लोधी एक ऐसी परंपरा के वाहक थे, जहाँ मातृभूमि की रक्षा को ही परम धर्म माना जाता था। वह केवल एक भूमिपति या जागीरदार नहीं थे, बल्कि अपनी प्रजा के सुख-दुख के साथी थे। 19वीं सदी के चौथे दशक तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी दमनकारी नीतियों और कुत्सित 'डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स' के माध्यम से भारतीय रियासतों को निगलना शुरू कर दिया था। जब अंग्रेजों की गिद्ध दृष्टि नरसिंहपुर और सागर क्षेत्र की उपजाऊ भूमि पर पड़ी, तब हिरदेशाह लोधी ने गुलामी को स्वीकार नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों के विरूद्ध अपनी तलवार उठा ली।

सन् 1842 में उत्तर और मध्य भारत के एक बड़े हिस्से में अंग्रेजों के खिलाफ जन-आक्रोश भड़क उठा, जिसे इतिहास में 'बुंदेला विद्रोह' के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह के मुख्य सूत्रधारों में राजा हिरदेशाह लोधी का नाम सबसे ऊपर आता है। उनके साथ जैतपुर के राजा परीक्षित और चंद्रपुर के जवाहर सिंह बुंदेला जैसे योद्धा भी थे। अंग्रेजों ने हीरापुर पर भारी लगान थोप दिया था और हिरदेशाह की पैतृक संपत्ति को जब्त करने की धमकी दी थी। स्वाभिमानी राजा ने अंग्रेजों के फरमान को ठुकराते हुए स्पष्ट कर दिया कि 'बुंदेलखंड की माटी का सौदा फिरंगियों के साथ कभी नहीं होगा।'

हिरदेशाह लोधी केवल साहसी ही नहीं थे, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी थे। उन्होंने भांप लिया था कि वे अंग्रेजों की आधुनिक तोपों का मुकाबला सीधे मैदान में नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने 'छापामार युद्ध' की नीति अपनाई। विंध्याचल के घने जंगलों और नर्मदा की घाटियों को उन्होंने अपना सुरक्षा कवच बनाया। उन्होंने अपनी सेना में न केवल लोधी समाज के युवाओं को शामिल किया, बल्कि गोंड, बुंदेला और स्थानीय आदिवासियों को भी एकजुट करके एक संयुक्त मोर्चा बनाया। यह उस दौर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। हिरदेशाह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के थानों को जला दिया, सरकारी खजानों को लूटा और संचार व्यवस्था को ठप कर दिया। कैप्टन वेकली और स्लीमन जैसे मंझे हुए अंग्रेज अधिकारी भी हिरदेशाह की चालों को समझने में नाकाम रहे।

राजा हिरदेशाह की लोकप्रियता का आलम यह था कि अंग्रेज सरकार ने उन पर भारी इनाम घोषित कर रखा था। इसके बावजूद, महीनों तक उनकी कोई पुख्ता जानकारी अंग्रेजों को नहीं मिली। स्थानीय लोग उन्हें 'जनता का राजा' मानते थे। यहाँ तक कि गाँवों की महिलाएं और किसान भी अंग्रेजों को गुमराह करने

के लिए गलत सूचनाएं देते थे। यह इस बात का प्रमाण है कि हिरदेशाह का संघर्ष केवल एक राजा की गद्दी बचाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह एक जन-आंदोलन था।

इतिहास गवाह है कि जब-जब भारतीय वीरों ने विदेशी ताकतों को घुटने टेकने पर मजबूर किया, तब-तब किसी न किसी 'जयचंद' ने पीठ में छुरा घोंपा। राजा रदेशाह लोधी के साथ भी यही हुआ। जब वे नर्मदा पार कर अपनी रणनीति बदल रहे थे, तब कुछ अपनों की गद्दारी और अंग्रेजों की घेराबंदी के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों ने उन्हें प्रलोभन देने की कोशिश की, माफी मांगने पर रियासत लौटाने का वादा किया, लेकिन उस वीर ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया।

आज जब हम 'आजादी का अमृत महोत्सव' मना रहे हैं, तब राजा हिरदेशाह लोधी जैसे नायकों का स्मरण करना और भी प्रासंगिक हो जाता है। उनके संघर्ष ने यह सिद्ध कर दिया था कि भारतीय जनमानस 1857 से बहुत पहले ही स्वतंत्रता के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुका था। 1842 का बुंदेला विद्रोह वह वैचारिक आधार बना, जिस पर आगे चलकर रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे योद्धाओं ने भव्य इमारत खड़ी की।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाठ्यपुस्तकों में राजा हिरदेशाह लोधी को वह स्थान नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे। नरसिंहपुर और आसपास के क्षेत्रों में आज भी लोकगीतों (आल्हा-ऊदल की तर्ज पर) में उनकी बहादुरी के किस्से सुनाए जाते हैं। अपने शौर्य और पराक्रम से राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में अपना अमूल्य योगदान देने वाले राजा हिरदेशाह लोधी जैसे महानायकों को राष्ट्रीय पटल पर प्रतिष्ठित करना आवश्यक है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ उनसे प्रेरणा ले सकें।

आज हमारा देश यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक पटल पर अपने शौर्य और पराक्रम का लोहा मनवा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पुनर्जागरण का दौर चल रहा है। ऐसे में भारतीय इतिहास के अदृश्य महानायकों को रेखांकित करने और राष्ट्रीय पटल पर प्रतिष्ठित करने का कार्य भी किया जा रहा है। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश के स्वाधीनता संग्राम में अपना बलिदान देने वाले और अपने रक्त से प्रदेश की पुण्य धरा को सिंचित करने वाले महानायकों को इतिहास के गुमनाम पन्नों से निकालकर वर्तमान के प्राक्कथन पर स्थापित करने का काम किया जा रहा है। राजा हिरदेशाह लोधी इसी पुनीत प्रक्रम के एक अभूतपूर्व व्यक्तित्व है, जिनके शौर्य का उद्घोष संपूर्ण मध्यप्रदेश कर रहा है।

राजा हिरदेशाह लोधी केवल एक ऐतिहासिक पात्र नहीं हैं, बल्कि वे अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध का प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि संसाधन कम होने पर भी यदि संकल्प दृढ़ हो, तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से भी टकराया जा सकता है। आज उनके बलिदान दिवस पर राष्ट्र उन्हें नमन करता है। उनके पदचिह्न हमें यह याद दिलाते रहेंगे कि आजादी की कीमत बलिदानों से चुकाई गई है और इसकी रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का परम कर्तव्य है।

ललित गद्य

रामावतार सागर

बेला का आगमन

बेला का परिचय बस इतना ही है कि ये आज उमड़ी है और कल चली जाएगी। 'न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की' की तर्ज़ पर जिसका जिक्र लगभग घर में रोज होता था वह आई भी तो मेहमान की तरह। हालांकि मुझे पालतू जीवों से सख्त नफ़रत तो नहीं है लेकिन मैं घर में रखने के पक्ष में भी नहीं हूं। लेकिन आज बेला का आना और चले जाना दोनों सुखकर है। 'बाईसा का फैरा पड़ गया, कुंअर साहब कि रिराटी मट गी' यूं तो बेला देखने में पहली ही नजर में बहुत प्यारी सी दिखी। एक दम सफेद झक्कास रंग पर काली बिल्लौरी आंखें। फ़िलहाल तो ये दो रंग उसके शरीर पर विद्यमान दिखलाई पड़े लेकिन असली रंग में तो उसका आना बाकी है जैसा कि मैंने चर्चाओं में सुना था। अभी उसके लिए ये घर नया है नये घर में तो शैतान से शैतान बच्चे भी कुछ देर शांत रहते हैं। इसकी अठखेलियां देखना बाकी रहा क्योंकि मेरा तो कॉलेज आने का समय हो गया है। फिर शाम को मिलते बेला के नये रूप के साथ। लेकिन इसके फोटो खिंचवाने के अंदाज से इतना तो तय हो गया कि ये कैमरा पसंद है। आप भी बेला के कुछ फोटोज देखिए और मुस्कुराइए.... ...

घर पर बेला का आगमन हुआ। बेला मतलब अलबेला खिलौना जो जीवित चलता-फिरता बिडाल है। अब तो आप समझ ही गये होंगे कि बेला एक बिल्ली नाम का प्राणी है,जो आज हमारे घर आया। इसका आना बिल्कुल भी अकस्मात् नहीं है बल्कि एक ज़िद थी, जो पूरी हुई। बेला और जिद का लंबा पुराण है जो घर में पिछले चार-पांच महीनों से चल रहा था और आज जिसका पटाक्षेप इस रूप में हुआ। बेला का परिचय बस इतना ही है कि ये आज उमड़ी है और कल चली जाएगी। 'न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की' की तर्ज़ पर जिसका जिक्र लगभग घर में रोज होता था वह आई भी तो मेहमान की तरह। हालांकि मुझे पालतू जीवों से सख्त नफ़रत तो नहीं है लेकिन मैं घर में रखने के पक्ष में भी नहीं हूं। लेकिन आज बेला का आना और चले जाना दोनों सुखकर है। 'बाईसा का फैरा पड़ गया, कुंअर साहब कि रिराटी मट गी' यूं तो बेला देखने में पहली ही नजर में बहुत प्यारी सी दिखी। एक दम सफेद झक्कास रंग पर काली बिल्लौरी आंखें। फ़िलहाल तो ये दो रंग उसके शरीर पर विद्यमान दिखलाई पड़े लेकिन असली रंग में तो उसका आना बाकी है (जैसा कि मैंने चर्चाओं में सुना

बेला के जाने की बेला
'खेलें बेला खेल निराले
घर में रेलमपेल निराले
थकती नहीं है इक पल यार
इसके भीतर सेल निराले
सबके पास है आती जाती
सबसे इसके मेल निराले
मार झपट्टा पंजा मारे
तीखे तीखे नेल निराले
इधर उधर चढ़ जाती झट से

देखो यारों गैल निराले'

दोस्तों! आज बेला विदा हो गयी। अल सुबह उसकी मालकिन का फोन आ गया सो देने जाना पड़ा। लेकिन इन बीतें 8 पहरों में बेला ने अठखेलियां की वह देखने में ज्यादा अच्छी है,लिखने के बजाय। मगर लिखना तो पड़ेगा मित्रों क्योंकि बगैर लिखे बेला के साथ अन्याय होगा। इन 24 घंटों में उसने घर भर को रोमांचित कर दिया। दिनभर उसको देखने वाले आते रहे और वह सहमति रही लेकिन अकेले होते ही एकदम से नटखट बिलार हो जाती। उसका खिलंदड़ापन एकाएक जागरूक हो जाता और मस्ती करने लगती है। दिनभर विडियो बनते रहे, फोटो खिंचते रहे और 'ले खींच मेरी फोटो' की तर्ज़ पर वह दिन भर पोज़ बनाती रही। और फिर शाम को उसके साथ खेलने के लिए पूरी एक टीम चली मेरे साथ नयापुरा से घर तक। दिन की बेसब्री को दबाये ये टीम बेहद उत्साहित थी बेला से मिलने के लिए। परिवार की बेटियां कैनिशा,पलक और संजना के साथ मिहिर बोस भी साथ रवाना हुए और फिर शुरू हुई रात को डेढ़ बजे तक की नोन स्टोप मस्ती

जिसके अनेक वीडियो भी आपके साथ सांझा करने हैं।

आने और जाने का संबंध भी अजीब है। जब बेला घर आई तो हमारी इच्छा नहीं थी कि आये और गयी तो भी हमारी इच्छा नहीं थी जाये। लेकिन 'कौन किसी को बांध सका,सय्याद इक भी दीवाना है' है कि तरहां ही उसको रोकना मुश्किल ही नामुमकिन साबित हुआ। कॉलेज हैं घर लौटता हूं तो देखता हूं कि बेला तो है ही नहीं।बेला का अलबेलापन भा गया मन को। रातभर किस तरह बेला को प्रियांशु ने संभाला यह तो ईश्वर ही जाने क्योंकि बेला को लाने वाला भी वही और वापस पहुंचाने वाला भी वही।इस लाने और ले जाने के बीच जो महत्वपूर्ण है वह है मानवीयता के रिश्ते जो भले ही एक पालतू के माध्यम से मजबूत हुए होंगे लेकिन बेला का यह अलबेलापन हमेशा फेसबुक की तारीखों में दर्ज हो गया। किसी बहाने से ही सही इस आभासीय पटल पर एक दस्तावेज़ दर्ज हुआ जो स्मृतियों में भी जीवित रहेगा। अब आप बेला के अनबेले विडियो देखिए और मुस्कुराइए क्योंकि यही एक नेमत है जो हमें इंसान बनाती है।

राजनीति

डॉ. भूपेन्द्र कुमार सुल्लेरे

दल-बदल: विचारधारा, अवसरवाद और लोकतांत्रिक संकट

प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा ने यह कहा कि 'मैं सही आदमी हूँ, लेकिन गलत पार्टी में हूँ।' यह कथन भारतीय राजनीति के उस अंतर्विरोध को उजागर करता है, जहाँ व्यक्ति स्वयं को सही ठहराते हुए संगठन को दोषी ठहराता है। उनके साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल जैसे नेताओं की उपस्थिति इस निर्णय को व्यक्तिगत न रखकर सामूहिक स्वरूप देती है। जब यह दावा किया जाता है कि राज्यसभा में पार्टी के दो-तिहाई सांसद उनके साथ हैं, तो यह केवल एक इस्तीफा नहीं, बल्कि एक संगठित राजनीतिक पुनर्संयोजन का संकेत बन जाता है। दूसरी ओर, अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे घटनाक्रम को 'पंजाबियों के साथ धक्का' बताया, जबकि संजय सिंह ने इसे 'ऑपरेशन लोटस' का हिस्सा करार दिया। 'ऑपरेशन लोटस' शब्द अब भारतीय राजनीति में एक प्रतीक बन चुका है, जिसका उपयोग विपक्षी दलों द्वारा यह आरोप लगाने के लिए किया जाता है कि सत्ताधारी दल अपने राजनीतिक विस्तार के लिए विपक्ष के नेताओं को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। इस संदर्भ में नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर लगाए गए आरोप राजनीतिक विमर्श को और अधिक तीखा बना देते हैं।

भारतीय लोकतंत्र को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, किंतु इसकी वास्तविक शक्ति केवल चुनावों में नहीं, बल्कि उस नैतिकता, विश्वास और वैचारिक प्रतिबद्धता में निहित होती है, जो जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाती है। हाल के राजनीतिक घटनाक्रम—विशेषकर राघव चड्ढा द्वारा आम आदमी पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा—ने इस नैतिक ढांचे को एक बार फिर प्रश्नों के घेरे में खड़ा कर दिया है। यह घटनाक्रम केवल एक राजनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति के चरित्र, दिशा और भविष्य को लेकर गहन विमर्श की मांग करता है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा ने यह कहा कि 'मैं सही आदमी हूँ, लेकिन गलत पार्टी में हूँ।' यह कथन भारतीय राजनीति के उस अंतर्विरोध को उजागर करता है, जहाँ व्यक्ति स्वयं को सही ठहराते हुए संगठन को दोषी ठहराता है। उनके साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल जैसे नेताओं की उपस्थिति इस निर्णय को व्यक्तिगत न रखकर सामूहिक स्वरूप देती है। जब यह दावा किया जाता है कि राज्यसभा में पार्टी के दो-तिहाई सांसद उनके साथ हैं, तो यह केवल एक इस्तीफा नहीं, बल्कि एक संगठित राजनीतिक पुनर्संयोजन का संकेत बन जाता है।

दूसरी ओर, अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे घटनाक्रम को 'पंजाबियों के साथ धक्का' बताया, जबकि संजय सिंह ने इसे 'ऑपरेशन लोटस' का हिस्सा करार दिया। 'ऑपरेशन लोटस' शब्द अब भारतीय राजनीति में एक प्रतीक बन चुका है, जिसका उपयोग विपक्षी दलों द्वारा यह आरोप लगाने के लिए किया जाता है कि सत्ताधारी दल अपने राजनीतिक विस्तार के लिए विपक्ष के नेताओं को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। इस संदर्भ में नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर लगाए गए आरोप राजनीतिक विमर्श को और अधिक तीखा बना देते हैं।

हालांकि, इस पूरे विवाद के बीच एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या यह वास्तव में राजनीतिक दबाव का परिणाम है या फिर एक वैचारिक असहमति का स्वाभाविक निष्कर्ष? राघव चड्ढा का यह दावा कि आम आदमी पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक चुकी है, एक गंभीर आरोप है। लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि क्या यह असहमति अचानक उत्पन्न हुई, या यह लंबे समय से पनप रही थी? भारतीय राजनीति में यह प्रवृत्ति देखी गई है कि जब नेता अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं, तब वे 'विचारधारा' का सहारा लेकर अपने निर्णय को वैधता देने का प्रयास करते हैं।

भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची, जिसे दल-बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, इस प्रकार की परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई थी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जनप्रतिनिधि अपने दल के प्रति निष्ठावान रहें और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दल-बदल न करें। लेकिन इस कानून में एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह भी है कि यदि किसी दल के दो-तिहाई सदस्य एक साथ दल बदलते

हैं, तो उन्हें अयोग्यता से छूट मिल सकती है। यही प्रावधान इस पूरे घटनाक्रम को संवैधानिक वैधता प्रदान करता है, भले ही नैतिक दृष्टि से यह विवादास्पद हो।

यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या यह कानून वास्तव में लोकतंत्र की रक्षा करता है, या यह राजनीतिक अवसरवाद को वैधता प्रदान करता है? कई संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रावधान 'सामूहिक दल-बदल' को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत दल-बदल पर तो रोक है, लेकिन समूह में किए गए दल-बदल को स्वीकार कर लिया जाता है। इस प्रकार, यह कानून अपने मूल उद्देश्य से भटकता हुआ प्रतीत होता है।

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा प्रभाव पंजाब की राजनीति पर पड़ सकता है, जहाँ भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार कार्यरत है। राज्यसभा के सांसदों का इस प्रकार दल बदलना न केवल पार्टी की आंतरिक स्थिरता को प्रभावित करेगा, बल्कि यह राज्य के राजनीतिक संतुलन को भी बदल सकता है। इससे यह भी संदेश जा सकता है कि पार्टी के भीतर असंतोष गहरा है, जो भविष्य में और बड़े राजनीतिक बदलावों का कारण बन सकता है।

राजनीतिक नैतिकता के संदर्भ में यह घटनाक्रम एक गंभीर संकट को उजागर करता है। जब नेता उस पार्टी को छोड़ते हैं, जिसके नाम पर वे जनता से वोट मांगकर सत्ता में आए थे, तो यह मतदाताओं के विश्वास को आहत करता है। संजय सिंह द्वारा इसे 'विश्वासघात' कहना और राघव चड्ढा द्वारा इसे 'आत्ममंथन का परिणाम' बताना—दोनों ही अपने-अपने दृष्टिकोण से सही हो सकते हैं, लेकिन सत्य इन दोनों के बीच कहीं स्थित है।

मीडिया की भूमिका भी इस पूरे घटनाक्रम में महत्वपूर्ण है। विभिन्न मीडिया संस्थान इसे अलग-अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे जनमत प्रभावित हो रहा है। सोशल मीडिया के इस युग में राजनीतिक नैरेटिव तेजी से बनते और बदलते हैं, और अक्सर तथ्य और भावनाएँ एक-दूसरे में घुलमिल जाती हैं। ऐसे में यह और भी आवश्यक हो जाता है कि जनता सूचनाओं का विवेकपूर्ण विश्लेषण करे।

अंततः, यह घटनाक्रम भारतीय लोकतंत्र के लिए एक चेतावनी है। लोकतंत्र केवल संवैधानिक प्रावधानों से नहीं चलता, बल्कि यह राजनीतिक नैतिकता, पारदर्शिता और जनविश्वास पर आधारित होता है। यदि दल-बदल की यह प्रवृत्ति इसी प्रकार बढ़ती रही, तो यह लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर सकती है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि राजनीतिक दल अपने आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करें, नेताओं को वैचारिक रूप से प्रशिक्षित करें और जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। साथ ही, संविधान में भी ऐसे सुधारों पर विचार किया जाना चाहिए, जो दल-बदल को केवल कानूनी ही नहीं, बल्कि नैतिक रूप से भी अस्वीकार्य बना सकें।

राघव चड्ढा का यह निर्णय केवल एक व्यक्तिगत या राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र के उस संक्रमणकाल का प्रतीक है, जहाँ सत्ता और सिद्धांत के बीच संघर्ष अपने चरम पर है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या भारतीय राजनीति इस चुनौती से उबर पाती है, या यह प्रवृत्ति लोकतंत्र के मूल्यों को और अधिक क्षीण कर देती है।

यातायात पुलिस की सीपीआर ट्रेनिंग देकर देवदूत बनी सुनीता पटेल, वृद्ध की बची जान

नर्मदापुरम्। पुलिस कि खाकी वर्दी अक्सर बदनाम होती पर सोशल पुलिसिंग में कुछ ऐसे मानवीय कार्य भी होते हैं जिससे किसी कि जान भी बच जाती है,वो भी महिला पुलिस अधिकारी कि ट्रेनिंग से जिस की जितनी सराहना कि जाए कम है, ऐसा ही एक मामला यहां आया, दरअसल डीजीपी कैलाश मकवाना के निर्देश पर समूचे प्रदेश में ट्रैफिक पुलिस द्वारा इमरजेंसी में सीपीआर देने कि ट्रेनिंग वाहन चालकों, किसानों, छात्रों व समाजसेवी लोगों को दी गई थीद्य नर्मदापुरम में इसकी जिम्मेदारी ट्रैफिक थाना प्रभारी

सुनीता पटेल को दी गई।

यातायात प्रभारी सुनीता पटेल ने एसपी सांई कृष्णा और एएसपी अभिषेक राजन के निर्देशन में तथा ट्रेफिक डीएसपी संतोष मिश्रा के मार्गदर्शन में सीपीआर देने की प्रक्रिया सिखाई थी। एक कृषक प्रमोद कुमार दुबे ने ट्रैफिक थाना प्रभारी सुनीता पटेल व उनके स्टाफ से एक माह पूर्व बस स्टैंड पर इमरजेंसी में सीपीआर देने की ट्रेनिंग ली थी। कुछ दिन पूर्व जगदीश मंदिर के पास राम मंदिर में भजन मंडली के वरिष्ठ सदस्य अम्बाप्रसाद कुशवाह वे भी भजन गा रहे थे। भजन समाप्त होने के बाद वे बैठते ही फर्श पर लुढ़क गए और उनकी स्थिति गंभीर हो गई।

प्रमोद कुमार दुबे ने ट्रेनिंग में बताए अनुसार कुशवाह को सीपीआर दिया और 10 मिनट बाद वे सामान्य हो गए। इस बीच उनके परिजन भी आ गए जो उन्हें डॉक्टर के पास ले गए और अब वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। दुबे ने बताया कि पुलिस कि इस ट्रेनिंग एक व्यक्ति कि जान बच गई निश्चित ही पुलिस कि यह ट्रेनिंग अनुकरणीय साबित हुई उन्होंने का हृदय से आभार व्यक्त किया है।

यातायात प्रभारी पटेल

मैंने बस स्टैंड के पास ट्रैफिक पुलिस को सीपीआर ट्रेनिंग देते देख मैं भी रुक गया था और ट्रेनिंग ले ली। यह मेरे जीवन की सबसे सुखद उपलब्धि रही जब हमारे साथी की जान बच गई, मैंने पटेल मैडम को हृदय से धन्यवाद दिया है। प्रमोद कुमार दुबे, औषधि कृषक ने मेरी जान बचाईद्य मैं और मेरा पूरा परिवार दुबे जी का व पुलिस विभाग का हृदय से आभारी है।

- अम्बा प्रसाद कुशवाहा सेनि कर्मचारी सिंचाई विभाग

क्या होता है सीपीआर

सीपीआर का मतलब है कार्डियोपल्मोनरी रेससिटेशन है। यह एक जीवनरक्षक तकनीक है, जिसका उपयोग तब किया जाता हैं जब किसी व्यक्ति का हृदय धड़कना बंद कर देता है या उसकी सांस रुक जाती है। सीपीआर में दो मुख्य चरण होते हैं। पहला, चेस्ट कंप्रेशंस इसमें व्यक्ति के सीने पर विशेष तरीके से दबाव डालकर हृदय को रक्त पंप करने में मदद की जाती है। दूसरा, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, इसमें व्यक्ति को सांस देने के लिए मुंह से हवा दी जाती है। सीपीआर का उद्देश्य व्यक्ति के मस्तिष्क और अन्य महत्वपूर्ण अंगों को ऑक्सीजनयुक्त रक्त प्रदान करना है जब तक कि चिकित्सा सहायता नहीं आती।

आवश्यकता है सोहागपुर में सीसीटीवी कैमरों की

सोहागपुर। विगत दिनों थार वाहन से साढ़े पांच लाख के थैले का मुख्य पहला कदम पुलिस को सीसीटीवी कैमरेस्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं केनरा बैंक के सीसीटीवी कैमरे में दिखाई देने वाली महिला थी। एसडीओ पुलिस ने पत्रकारों को बताया कि महिला की फोटो अन्य थानों में भेजी गई। जिसमें राजगढ़ जिले में उनको अंतराज्यीय गिरोह होने का संदेह मिला। इसी आधार सोहागपुर पुलिस सफलता प्राप्त हुई।नगर में संदिग्ध गतिविधियों एवं अपराधिक मामलों में सीसीटीवी कैमरे की उपयोगिता अति आवश्यक है। हालांकि पूर्व नपाध्यक्ष संतोष मालवीय ने इस मामले में गति आगे बढ़ाई थी। लेकिन वह धरातल पर नहीं उतरी। हाल ही में क्षेत्रीय विधायक विजयपालसिंह ने स्थानीय विश्राम गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा था कि अगले दो महीने में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए समाजसेवियों से भी सहयोग लिया जाएगा। इधर आज एसडीओ पुलिस संजू चौहान ने जन-मानस से आग्रह किया है कि बैंक से बड़ी राशि निकालते समय सावधानी बरतें एवं संदिग्ध व्यक्तियों एवं संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दें। आपने व्यवसायियों से कहा है कि अपने-अपने प्रतिष्ठानों के आवागमन स्थल पर सीसीटीवी कैमरा स्थापित करें । ऐसी वारदातों पर अंकुश लगाने में पुलिस को सहयोग प्राप्त हो।

पेंशनरों ने जनवरी 26 से 2% डीआर मांगा

भोपाल। सरकार कार्मिक व लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग का परिपत्र क्रमांक 42/2/2024-पी एण्ड पीडब्ल्यू (डी) 9475 दि.-24 अप्रैल 2026 को संदर्भित कर मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव वित्त को पत्र लिखकर भारत सरकार के समान प्रदेश के पेंशनरों को 1 जनवरी 2026 से 2% महंगाई राहत देने की मांग की है । पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी एवं प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि सरकार को ज्ञात होना चाहिए कि भारत सरकार के अनुरूप प्रदेश के पेंशनरों को महंगाई राहत देने की व्यवस्था संवैधानिक रूप से समर्थित है और यह सरकारी नीति का एक अनिवार्य हिस्सा है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पुख्ता किया है ।

सक्सेना ने बताया कि भारत सरकार के पेंशनरों के विपरीत प्रदेश के पेंशनरों को 1 जुलाई 19 से लगातार महंगाई राहत की दर एवं अवधि में कटौती/अंतर किया जा रहा है, जो मूलभूत अधिकार (अनुच्छेद 14) समानता के अधिकार का उल्लंघन है । महंगाई राहत को पेंशन भोगी के जीवन और जीविका के अधिकार से जोड़ा गया है, जो अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षित है। भोपाल जिले के अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा (चंडीगढ़) केरल, महाराष्ट्र (मुंबई) द्वारा अपने निर्णय में डी आर को संवैधानिक बताते हुए केंद्रीय तिथि से भुगतान के आदेश पारित किए हैं । सुरेश शर्मा ने कहा कि डी आर की दर एवं अवधि में मनमानी अंतर/कटौती करना अनुच्छेद 14 का स्पष्ट उल्लंघन है । संगठन के प्रांतीय उपाध्यक्ष संतोष ठाकुर, शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव प्रांतीय सचिव रामगोपाल माथुर, यशवंत सिंह बेस ने कहा कि केंद्रीय पेंशनर एवं राज्य के पेंशनर में अंतर करना असंवैधानिक है, क्योंकि दोनों पर महंगाई का प्रभाव समान रूप से पड़ता है ।

भीषण गर्मी भी नहीं रोक पाई आस्था, सैकड़ों गौभक्तों की मौजूदगी में निकली गौ सम्मान पदयात्रा

राष्ट्रमाता दर्जा, वध पर पूर्ण प्रतिबंध और सख्त कानून की मांग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

बैतूल। सोमवार को बैतूल शहर में विराट गौ सम्मान पदयात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में गौभक्त शामिल हुए। भीषण गर्मी भी गौभक्तों के हौसले को पस्त नहीं कर पाई। राष्ट्रमाता का दर्जा देने, गोवंश वध पर पूर्ण प्रतिबंध और सख्त केंद्रीय कानून बनाने की मांग को लेकर गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत यह पदयात्रा सुबह 11 बजे नगर के शिवाजी ऑडिटोरियम से शुरू होकर तहसील कार्यालय पहुंची, जहां महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार बैतूल को ज्ञापन सौंपा गया। पदयात्रा में भजन-कीर्तन और प्रार्थना के साथ शांतिपूर्ण तरीके से गौभक्त आगे बढ़े और इस दौरान आस्था का माहौल देखते ही बन रहा था। 9 सूत्रीय मांग पत्र में गौ संरक्षण, गौशालाओं को सहायता, गौ अभ्यारण्य निर्माण, तस्करी पर सख्त कानून और आधुनिक गौ चिकित्सालय स्थापित करने सहित गोवंश को राष्ट्रमाता का संवैधानिक दर्जा देने की मांग प्रमुख रूप से रखी गई। गौ भक्तों द्वारा सौपे गए ज्ञापन में बताया गया कि भारतीय संस्कृति, प्राकृतिक कृषि, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था की आधारशिला मानी जाने वाली गोमाता आज सडक़ों, खेतों और गलियों में कष्टपूर्ण स्थिति में भटक रही है। भूख, दुर्घटनाओं, तस्करी और वध के कारण देशी गोवंश की संख्या लगातार घट रही है, जो गंभीर चिंता का विषय है। ज्ञापन में वर्ष 1966 के गोरक्षा आंदोलन का उल्लेख करते कहा गया कि लंबे समय से गोसंरक्षण को लेकर अपेक्षित कदम नहीं उठाए गए, जबकि अब समय निर्णायक नीति बनाने का है। इसमें प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए गोमाता को संवैधानिक संरक्षण और राष्ट्रीय सम्मान देने की मांग की गई। प्रस्ताव में गोवंश वध और तस्करी को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध घोषित कर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान करने, अपराध में प्रयुक्त संपत्ति और वाहनों को राजसात करने तथा पशुपालन विभाग से अलग स्वतंत्र गो-पालन मंत्रालय बनाने की मांग की गई। साथ ही इस सम्बंध में पूरे देश में एक समान केंद्रीय कानून लागू करने का सुझाव दिया गया। आर्थिक और कृषि क्षेत्र में पंचगव्य अनुसंधान केंद्र स्थापित करने, गोबर और गोमूत्र आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने और किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया। गो आधारित उत्पादों के लिए बाजार व्यवस्था विकसित करने और सरकारी संस्थानों में इनके उपयोग को अनिवार्य करने की भी बात ज्ञापन में कही गई।

बुनियादी ढांचे में प्रत्येक जिले में गो अभयारण्य, ग्राम पंचायत स्तर पर नंदीशाला, गोशालाओं को अनुदान, चारा प्रबंधन और गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का प्रस्ताव शामिल है। इसके साथ ही बायोगैस प्लांट के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन और मृत गोवंश के सम्मानजनक अंतिम संस्कार की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग रखी गई। स्वास्थ्य और सुरक्षा के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर गो-एम्बुलेंस, ट्रॉमा सेंटर और गो चिकित्सालय स्थापित करने, प्रत्येक जिले में पंचगव्य चिकित्सालय खोलने, स्कूलों के पाठ्यक्रम में गोवंश का महत्व शामिल करने और मध्याह्न भोजन योजना में गो-दुग्ध उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया। सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर मंदिरों में केवल देशी गो उत्पादों के उपयोग, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड का हिस्सा गो सेवा में लगाने, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध और डीजल, पेट्रोल, टोल टैक्स जैसी सेवाओं पर गो-सेस लागू कर गो कल्याण कोष बनाने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है। अभियान की कार्ययोजना के अनुसार 27 अप्रैल को तहसील स्तर पर ज्ञापन सौंपने के बाद मई से जुलाई तक शासन से संवाद किया जाएगा। इसके बाद जुलाई, अक्टूबर और आगे राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन बढ़ाया जाएगा। मांगें पूरी नहीं होने पर 2027 में नई दिल्ली में विशाल, अहिंसक जनआंदोलन, संकीर्तन और प्रार्थना के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाया जाएगा। आयोजकों ने स्पष्ट किया कि यह अभियान किसी राजनीतिक दल के नेतृत्व में नहीं है, गोमाता को प्रधान संरक्षक और नंदी को प्रतीकात्मक अध्यक्ष मानकर देशभर के संत समाज, गोभक्त, गोशाला संचालक और नागरिकों द्वारा स्वस्फूर्त रूप से संचालित किया जा रहा है।

गौसेवकों ने पीएम-सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

गौ सम्मान आव्हान अभियान के अंतर्गत भैंसदेही के गौ-सेवकों ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित ज्ञापन तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार भगवानदास कुमरे को सौंपा। जिसमें गौ-सेवकों ने मांग की है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर नंदीशाला और जिला स्तर पर न्यूनतम एक आदर्श गो अभ्यारण अथवा वृहद गोशाला की स्थापना अनिवार्य हो, जहां निराश्रित गौवंश को ससम्मान आश्रय मिल सके। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल रहे।

गौ सेवकों ने गौ सम्मान आह्वान अंतर्गत पत्रक सौंपा

बैतूल/शाहपुर। सोमवार को देशभर के गौ सेवकों ने गौ सम्मान आह्वान अभियान के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन/ पत्रक सौंपा गया। इसी तारतम्य में शाहपुर नगर के गौ सेवकों ने हस्ताक्षर पत्र के साथ एसडीएम तहसील कार्यालय शाहपुर पहुंचकर भारत में गौ माता को उचित सम्मान देने की मांग को लेकर पत्रक दिया गया। इस अवसर पर शाहपुर क्षेत्र के गोभक्त बड़ी संख्या में शामिल रहे।

बैतूल में 43 डिग्री पहुंचा तापमान, स्कूल बंद, आंगनबाड़ियों का हो रहा संचालन

बैतूल। जिले में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। सोमवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रविवार को तापमान 43 डिग्री था। अधिकतम तापमान में अचानक उछाल के कारण लोगों को तेज लू और झुलसा देने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार तापमान में बढोत्तरी और तेज धूप के कारण दोपहर के समय सडक़ों पर आवाजाही काफी कम देखी गई, लोग केवल आवश्यक कार्यों के लिए ही घरों से बाहर निकले रहे है। भोपाल मौसम केंद्र द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मध्यप्रदेश के कई हिस्सों सहित बैतूल में अगले दो दिनों तक हीटवेव (लू) की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर गरज-चमक और आंधी की भी आशंका जताई गई है, हालांकि इससे तापमान में खास राहत मिलने के आसार कम हैं।

एंटी-साइक्लोनिक सिस्टम के कारण बढ़ रही गर्मी..- जिले में तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना हुआ है। आसमान साफ होने और एंटी-साइक्लोनिक सिस्टम के कारण गर्मी और

तेज हो रही है। इस भीषण गर्मी का सबसे अधिक असर मजदूर, किसान और खुले में काम करने वाले लोगों पर पड़ रहा है, जहां दोपहर में लू के थपेड़े उनके स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रहे हैं। प्रशासन और मौसम विभाग ने नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। लोगों से दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचने, अधिक से अधिक पानी पीने और सिर ढककर ही घर से बाहर निकलने का आग्रह किया गया है।

नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल बंद, इधर आंगनबाड़ियां चालू..

बैतूल जिले में भीषण गर्मी के कारण प्रशासन ने नर्सरी से आठवीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने यह आदेश जारी किया है। जारी आदेश के तहत, जिले के सभी शासकीय, अशासकीय, सीबीएसई, आईसीएसई, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय सहित अन्य शिक्षण संस्थानों में नर्सरी से कक्षा आठवीं तक की कक्षाएं अगले आदेश तक बंद रहेंगी, लेकिन जिले में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद नहीं किया गया है। इन केंद्रों में 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों को पोषण आहार के साथ अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। बच्चे सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक यहां रहते हैं, जबकि स्टाफ के लिए संचालन दोपहर 3 बजे तक होता है। अधिकांश केन्द्रों पर गर्मी से बचाव के लिए सुविधाओं की भारी कमी देखी जा सकती है।

सोहागपुर पुलिस की सफलता: जिला राजगढ़ के थाना बोड़ा ग्राम कड़िया सांसी बस्ती की महिला से पुलिस टीम ने साढ़े पांच लाख रुपये बरामद किए

सोहागपुर। सोहागपुर के केनरा बैंक के सामने खड़ी थार वाहन से साढ़े पांच लाख रुपये से भरा थैला गायब होने के सनसनीखेज मामले एसडीओ पुलिस कार्यालय में खुलासा पत्रकार वार्ता में किया गया। उक्त मामला नगर में काफी चर्चित हो गया था। इस तरह की वारदात होने से व्यापारियों में चिंता की लहर फ़ैल गई थी। इस गंभीर मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करके वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लिया था। जिसमें पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम श्री सांई कृष्णा एस थोटा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक रंजन के निर्देशन में तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री संजू चौहान के मार्गदर्शन में शीघ्र विशेष पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम घटना के बाद से शहर में प्रमुख स्थानों एवं संभावित मार्गो के सीसीटीवी फुटेज एकत्रित कर उनका सूक्ष्म विश्लेषण किया गया। साथ ही मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। एसडीओ पुलिस संजू चौहान एवं नगर निरीक्षक राहुल रायकवार ने पत्रकारों को बताया कि

दिनांक 23. अप्रैल 26 को थाना सोहागपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आवेदक पराग शर्मा पिता श्याम शर्मा, निवासी सेमरी

हरचंद, व्यवसाय अनाज व्यापारी ने मामले की रिपोर्ट की थी कि उनका अकाउंटेंट तिलक मालवीय पिता नितिन मालवीय (अकाउंटेंट) तथा परिचित सिद्धार्थ चौधरी एवं सौरभचौधरी (सर्वेयर) के साथ बैंक कार्य हेतु थार गाडी से सोहागपुर बैंक गये थे। सिद्धार्थ एवं सौरभ चौधरी के नाम रजिस्ट्री होना प्रस्तावित थी। जिसके लिए सभी लोग बैंक आए थे। आवेदक ने साढ़े पांच लाख भारतीय स्टेट बैंक से निकालकर केनरा बैंक अन्य कार्य के लिए गए थे। फरियादी ने केनरा बैंक के सामने वाहन खड़ा कर सभी लोग बैंक के अंदर चले गए। संयोग से थार वाहन को लाक करना भूल गए।जब वापिस आए तो पैसों से भरा थैला गायब मिला । पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया। जिसमें एक महिला को संदिग्ध परिस्थितियों में थार वाहन के पास निकलते देखा गया। इसी संदेह पर पुलिस की सुई महिला पर केंद्रित हो गई। उक्त महिला को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रेल्वे स्टेशन ब्रांच के फिटेज में भी दिखाई दी। सीसीटीवी फुटेज एवं राजगढ़ जिले में ऐसी ही वारदातों को अंतराज्यीय गिरोह अंजाम देते हैं। ऐसी ही कड़ी नवनियुक्त नगर निरीक्षक राहुल रायकवार भी राजगढ़ जिले के थाने पदस्थ रहे चुके थे ने जोड़ दी। बाद में सोहागपुर पुलिस टीम राजगढ़ जिले को रवाना हुई। टीम के सघन प्रयासों के उपरांत जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त घटना को राजगढ़ जिले के थाना बोड़ा क्षेत्र के कड़िया सांसी गांव निवासी महिला सुधा उर्फ सुगना पति अजब सिंह उर्फ हरवीर द्वारा अंजाम दिया गया है। यहां पुलिस की गठित टीम ने ग्राम कड़िया सासी थाना बोडा जिला राजगढ़ में दबिश दी गई। पुलिस की तत्कालीन निर्णय से आरोपी महिला से सम्पूर्ण साढ़े पांच लाख बरामद करके आरोपी महिला को अभिरक्षा में लिया गया ।

तात्कालिक निर्णय - सोहागपुर पुलिस के तात्कालिक निर्णय से रायगढ़ जिले से परी राशि साढ़े पांच लाख रुपये बरामद हुए।

सक्रिय योगदान - पुलिस टीम के निरीक्षक राहुल रायकवार, उपनिरीक्षक राहुल पटेल, सहायक उपनिरीक्षक मनोज राजपूत, प्रधान आरक्षक विनोद नागर, महिला प्रधान आरक्षक मंजूलता परते, आरक्षक मनोहर दायमा, आरक्षक राजकुमार यादव आरक्षक विवेक सोनपुरे, आरक्षक सुनील ओझा की उल्लेखनीय भूमिका रही

नवीन खेती अपनाएं, योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं - कलेक्टर का किसानों से आह्वान

सहकारी बैंकिंग और नई कृषि तकनीक से सशक्त बनें किसान, कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए निर्देश

- हर किसान तक पहुंचे योजना का लाभ, आधुनिक खेती के लिए प्रेरित करें कृषि अधिकारी
- योजनाओं का क्रियान्वयन केवल कागजों तक न रहे सीमित – कलेक्टर
- जिला सहकारी बैंक वर्ष 2026 में 10.34 करोड़ रुपए के लाभ में
- कलेक्टर ने की कृषि, सहकारिता, उद्यानिकी, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग की गतिविधियों की समीक्षा

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में कृषि, सहकारिता, उद्यानिकी, मत्स्य, मार्कफेड एवं पशुपालन विभाग की गतिविधियों एवं कार्यप्रगति की गहन समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय-सीमा में पहुँचना चाहिए और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फील्ड स्तर पर निगरानी मजबूत की जाए और योजनाओं का क्रियान्वयन केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका प्रभाव सीधे किसानों और आमजन के जीवन में दिखाई देना चाहिए।

बैंकिंग व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश

बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरु के ने जिला सहकारी बैंक की बैंकिंग व्यवस्था मजबूत करने और किसानों को अधिक सुविधा और राहत देने की बात कही। सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि सीहोर की जिला सहकारी केंद्रीय बैंक वर्ष 2026 में लगभग 10.34 करोड़ रुपए के वार्षिक लाभ में है तथा नाबार्ड से पुनर्वित्त के लिए पात्र है। पैक्स के कम्प्यूटरीकरण, ईआरपी एंट्री एवं ई-पैक्स व्यवस्था के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही कालातीत कृषि ऋणों की वसूली के लिए रिस्ट्रक्चरिंग योजना लागू की जा रही है।

मत्स्य विभाग की योजनाओं का अधिक से अधिक हितग्राहियों को मिले लाभ : कलेक्टर श्री बालागुरु के ने मत्स्य विभाग की समीक्षा में निर्देश दिए कि जिले के जल संसाधनों का प्रभावी उपयोग उपयोग किया जाए और अधिक से अधिक हितग्राही लाभान्वित हो सके । बैठक में जानकारी दी गई थी 328 ग्रामीण तालाब एवं 69 सिंचाई जलाशयों में 100 प्रतिशत क्षेत्र में मत्स्य पालन किया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में मत्स्योत्पादन के लिए 347 टन के लक्ष्य के विरुद्ध 326.30 टन उत्पादन हासिल कर 94 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई है।

किसानों को जागरूक करने और जैविक कृषि की ओर अग्रसर करने के लिए निर्देश

बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरु के ने कृषि अधिकारियों को किसानों को कृषि क्षेत्र में आ रहे बदलाव की त्वरित जानकारी पहुंचाने और नवीनतम कृषि पद्धतियों की जानकारी देकर उन्हें जागरूक करने के निर्देश दिए। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान वर्ष 2026-27 के लिए कृषि योजना के अंतर्गत खरीफ एवं रबी फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता के लक्ष्य निर्धारित किए गए। खरीफ 2026 के लिए बीज, उर्वरक एवं पौध संरक्षण दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से अधिक से अधिक किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच कर उन्हें उर्वरक उपयोग की वैज्ञानिक सलाह देने पर जोर दिया गया। नरवाई प्रबंधन के अंतर्गत हैप्पी सीडर एवं सुपर सीडर मशीनों की उपलब्धता बढ़ाने तथा ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए गए, जिससे जल संरक्षण के साथ उत्पादकता में वृद्धि हो सके।

दुग्ध उत्पादन और संग्रहण में वृद्धि की जाए

कलेक्टर श्री बालागुरु के ने पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान कहां की किसानों के लिए पशुपालन आय का अतिरिक्त साधन है ।किसानों को पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाए और शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलाया जाए। पशुपालन एवं दुग्ध विकास गतिविधियों की समीक्षा में सहकारी समितियों के माध्यम से दुग्ध उत्पादन एवं संग्रहण में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई।

नर्मदापुरम में बस की टक्कर से पलटा लोडिंग ऑटो:

इटारसी के मजदूर की मौत, 2 घायल

नर्मदापुरम(निप्र)। नर्मदापुरम-पिपरिया स्टेट हाईवे पर आशीर्वाद कॉलोनी के पास शनिवार शाम करीब 6:45 बजे एक यात्री बस ने लोडिंग ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो पलट गया और उसमें पीछे बैठे इटारसी निवासी एक मजदूर युवक की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हैं। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने 'जय माता दी ट्रैवल्स' की बस पर पथराव कर कांच फोड़ दिए और ड्राइवर-कंडक्टर के साथ मारपीट की। सूचना पर देहात थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया और घायलों को अस्पताल भेजा। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और रविवार सुबह मृतक का पोस्टमार्टम किया जाएगा।

टेंट का सामान छोड़कर लौट रहे थे सभी मजदूर : घायल कर्तव्य ने बताया कि वे सभी इटारसी में मनोज के पास टेंट हाउस लगाने का काम करते हैं। शनिवार शाम वे नर्मदापुरम के मालाखेड़ी में टेंट का सामान छोड़ने आए थे। वहां से सभी ऑटो में बैठकर लौट रहे थे।

मनोज ऑटो चला रहा था और उसके साथ आगे ऋतिक बैठा था। पीछे की तरफ सत्यम नर्रे, केशव और कर्तव्य बैठे थे। तभी बस ने ऑटो को टक्कर मार दी।

सिर और मुंह में चोट लगने से सत्यम की गई जान : टक्कर लगने से पीछे बैठे सत्यम के सिर और मुंह में गंभीर चोट आई और वह अचेत हो गया। जिला अस्पताल लाने पर डॉक्टर ने चेक कर उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे में केशव और कर्तव्य को भी चोटें आई हैं, जिनका इलाज जारी है। ऑटो चला रहे मनोज और आगे बैठे ऋतिक को चोट नहीं आई है। टक्कर मारने वाली बस यात्रियों से भरी थी। एक्सीडेंट के बाद बस रुकते ही कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और वे नीचे उतर गए।

संक्षिप्त समाचार

एसडीएम ने खड़ेर आयुष औषधालय का किया निरीक्षण, 23 मरीजों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण

विदिशा (निप्र)। नटेरन एसडीएम अजय प्रताप सिंह पटेल द्वारा आज ग्राम खड़ेर में स्थित आयुष औषधालय का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संस्थान में पदस्थ समस्त स्टाफ उपस्थित पाया गया, जिस पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। निरीक्षण के समय औषधालय में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान कुल 23 व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। एसडीएम ने चिकित्सकीय व्यवस्थाओं, दवाओं की उपलब्धता एवं मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जाए, ताकि आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। साथ ही मरीजों को समय पर उपचार एवं आवश्यक मार्गदर्शन देने पर विशेष जोर दिया। एसडीएम ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप आयुष औषधालयों के माध्यम से ग्रामीणों को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है, जिसके लिए नियमित निरीक्षण जारी रहेंगे।

नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा अंतर्गत पॉलिटेक्निक कॉलेज में अनेक गतिविधियां आयोजित

सीहोर (निप्र)। सीहोर के शासकीय महिला पॉलीटेक्निक कॉलेज में नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा के अंतर्गत 10 अप्रैल से 25 अप्रैल 2026 तक अनेक गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस दौरान 'नारी शक्ति वंदन' विषय पर विशेष व्याख्यान, विचार-विमर्श, पोस्टर प्रतियोगिता, नारा लेखन प्रतियोगिता, प्रस्तावना का सामूहिक वाचन सहित अनेक गतिविधियां आयोजित की गईं। 25 अप्रैल को इन गतिविधियों के समापन पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर एसडीओ सुश्री पूजा शर्मा ने छात्राओं को स्वाभिमान, आत्मसम्मान एवं सुरक्षा के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या अनुचित घटना होने पर बिना संकोच तुरंत पुलिस को सूचना दें, जिससे समय पर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. प्रमोद शर्मा एवं डॉ. पंकज जैन उपस्थित थे।

रोल प्ले के माध्यम से प्रस्तुत किए नागरिकों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों एवं शंकाओं के संतोषजनक समाधान

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. के निर्देशानुसार भैरूंदा तहसील में जनगणना 2027 के तृतीय एवं अंतिम चरण के प्रशिक्षण का समापन हुआ। प्रशिक्षण में 143 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया, जिन्हें 6 फील्ड प्रशिक्षकों द्वारा प्रतिदिन प्रातः 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के समापन अवसर पर प्रतिभागियों ने रोल प्ले के माध्यम से फील्ड में नागरिकों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों एवं शंकाओं के संतोषजनक समाधान प्रस्तुत किए।

आंगनवाड़ी केन्द्र पर महिला जागरूकता कार्यक्रम सम्पन्न

हरदा (निप्र)। वन स्टॉप सेंटर हरदा द्वारा शनिवार को ऑगनवाड़ी केन्द्र क्रमांक 01, हरदा में समापन दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर की केस वर्कर सुश्री रितु राजपूत ने महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा, बाल विवाह निषेध, दहेज प्रथा उन्मूलन तथा राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। इसके साथ ही 'हब फॉर एंपावरमेंट' के अंतर्गत महिलाओं से संबंधित स्वरोजगार योजनाओं पर भी प्रकाश डाला गया। वन स्टॉप सेंटर द्वारा उपलब्ध सेवाओं जैसे परामर्श सहायता, विधिक सहायता, आश्रय सहायता, चिकित्सा सहायता एवं पुलिस सहायता की जानकारी दी गई।

जिला जेल में विशेष स्वास्थ्य परीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

बैतूल (निप्र)। जिला जेल बैतूल में 25 अप्रैल को विशेष स्वास्थ्य परीक्षण तथा विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव सचदेवा, मुख्य न्यायाधिपति मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा किया गया। इस अवसर पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय जबलपुर के अध्यक्ष एवं न्यायमूर्ति श्री विवेक अग्रवाल एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। जिला जेल बैतूल में विशेष स्वास्थ्य परीक्षण तथा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश /अध्यक्ष श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल के निर्देशन में किया गया। विधिक साक्षरता शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विधिक सहायता अधिकारी श्री सोमनाथ राय एवं लीगल एड डिफेंस काउंसल के द्वारा बंदियों से उनके प्रकरणों की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक सलाह दी गई। इसके अतिरिक्त उन्होने बंदियों के लिये निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा तथा अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी द्वारा किये जाने वाले कार्यों की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में जिला चिकित्सालय के चिकित्सक डॉ. गौरव कंच-सर्जिकल विशेषज्ञ, डॉ. रोहित परते चिकित्सा अधिकारी (मेडिसिन), डॉ. वंदना धाकड, स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉ. सायमा रिजवी, दंत रोग विशेषज्ञ, डॉ. संजय खातरकर, मनोरोग विशेषज्ञ, डॉ. शीतल मर्सकोले., नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं डॉ. रूपेश पद्माकर, अस्थि रोग विशेषज्ञ के द्वारा पुरूष व महिला बंदियों की जाँच की गई। शिविर में कुल 501 बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया एवं सभी बंदियों को हेल्थ कार्ड प्रदान किये गये। इस अवसर पर जेल अधीक्षक श्री योगेन्द्र तिवारी, लीगल एड डिफेंस काउंसल श्री श्याम किशोर शुक्ला, श्री ऐजाज खान, श्री सुरेश कुमार राकसे, श्री सुनील मोर, श्री मंगल सिंह परिहार, श्री राघवेन्द्र रघुवंशी तथा श्री राजेश शेषकर एवं जेल कर्मचारी मौजूद रहें।

विश्व मलेरिया दिवस पर विविध गतिविधियों का हुआ आयोजन

हरदा (निप्र)। जिले को मलेरिया बीमारी से मुक्त करने के लिये प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 25 अप्रैल 2026 को ''विश्व मलेरिया दिवस'' मनाया गया। जिला मुख्यालय हरदा में मच्छरजन्य बीमारियों से बचाव, नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु शपथ दिलाई गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एच.पी.सिंह ने बताया कि मलेरिया से मुक्ति के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना है, इसके लिये भारत शासन द्वारा वर्ष 2026 में विश्व मलेरिया दिवस की थीम ''मलेरिया समाप्ति के लिए संकल्पितः अब हम कर सकते है, अब हमें करना ही होगा'' पर कार्य किया जाना है। शनिवार को विश्व मलेरिया दिवस के उपलक्ष्य में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हरदा में आशा कार्यकर्ताओं की कार्यशाला का आयोजन कर लार्वा सर्वे कार्य एवं फीवर सर्वे कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। विश्व मलेरिया दिवस पर जिला मुख्यालय एवं स्वास्थ्य संस्थाओ में शपथ आयोजन, नारे लेखन कार्य, एवं प्रचार-प्रसार कार्य एवं आमजन में मच्छरजनित बीमारियों के बचाव संबंधी जनजागरूकता हेतु माईकिंग कार्य एवं पंपलेट्स वितरण कार्य कराया जा रहा है। डॉ. सिंह ने बताया कि जिले में मलेरिया उन्मूलन हेतु सभी स्वास्थ्य संस्थाओ में बुखार के मरीजो की मलेरिया जॉच एवं उपचार निःशुल्क की जा रही है। ग्राम स्तर पर आशा कार्यकर्ताओं एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओ के द्वारा घर-घर जाकर मलेरिया रैपिड डायग्नोस्टिक किट के माध्यम से मलेरिया की जॉच की जा रही है।

क्या है मलेरिया

सीएमएचओ डॉ. सिंह ने बताया कि मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के संक्रमण से होने वाला संक्रामक रोग है, जो स्वस्थ्य मनुष्य में संक्रमित मादा एनोफिलिज मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया की रोकथाम एवं इलाज संभव है, किन्तु समय पर जॉच एवं उपचार न लेने पर जानलेवा हो सकता है। कंपकंपी वाली ठंड लगकर बुखार आना, सिरदर्द, जी मिचलना एवं उल्टी, मांसपेशियों एवं जोडों में दर्द, थकान एवं कमजोरी, पसीना आकर बुखार उतरना आदि मलेरिया के प्रमुख लक्षण है। यह एक जानलेवा बीमारी है, जो कि संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से फैलती है। संक्रमित मच्छरों में प्लाज्मोडियम परजीवी होते है। जब यह मच्छर काटता है तो परजीवी आपके खून में मिल जाते है।

मलेरिया का उपचार

डॉ. सिंह ने बताया कि मलेरिया के लक्षण दिखाई देने पर खून की जॉच कराये। मलेरिया की जॉच एवं उपचार सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता के पास निःशुल्क उपलब्ध है। यह बरसात के मौसम में मुख्य रूप से फैलता है। मच्छर भरे हुए साफ पानी में पनपते है। मलेरिया से बचाव हेतु मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए पानी को जमा नही होने दें, मच्छरनाशी दवाईयों का छिडकाव करें, सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें, पूरी आस्तीन के कपडे पहनें, पानी के बर्तनो, मटकों एवं टंकियों को अच्छी तरह ढक कर रखें, घर के मुख्य दरवाजे पर मच्छररोधी जाली लगाये, शाम को मच्छर भगाने हेतु नीम की पत्ती का धुँआ, क्वाईल या रिपेलेंट का उपयोग करें।

मंत्री श्री पटेल ने नर्मदा गुंजारी घाट पर चल रहे कार्य का किया निरीक्षण

सीहोर (निप्र)। पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत बुधनी जनपद के ग्राम जोशीपुर में गुंजारी नर्मदा संगम घाट पर चल रहे पुनर्निर्माण एवं नवसंवार कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अभी तक की कार्य प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देशित किया कि संगम स्थलों की स्वच्छता, सौंदर्यीकरण एवं संरक्षण के कार्य नियमित रूप से जारी रखें। उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की कि वे जल स्त्रोतों को स्वच्छ बनाए रखने में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।

सीएमएचओ ने स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं में सुधार के दिए निर्देश

बैतूल (निप्र)। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज कुमार हुरमाड़े ने जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. प्रांजल उपाध्याय के साथ शनिवार को विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य केन्द्र महूपानी में सीएचओ उपस्थित पाई गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दामजीपुरा के निरीक्षण के दौरान चिकित्सा अधिकारी श्री पंकज उइके द्वारा मरीजों का उपचार किया जा रहा था। यहां स्टोर में दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध मिलीं। सीएमएचओ ने ओपीडी, टीकाकरण पंजी, वार्ड एवं मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का निरीक्षण कर गर्भवती एवं हाई रिस्क महिलाओं की जानकारी ली तथा चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए। इसके बाद सीएमएचओ डॉ हुरमाड़े ने कामोद एवं झाकस उप स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण कर एएनसी रजिस्टर , एनसीडी रजिस्टर, एचपीवी वैक्सीन, परिवार नियोजन, टीकाकरण की स्थिति, हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की जानकारी ली। वहीं प्रतिमाह 9 एवं 25 तारीख को आयोजित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में हाई रिस्क महिलाओं को आवश्यक रूप ले जाने के निर्देश दिये। साथ ही दस्तक अभियान के दौरान चिन्हित ऐनीमिक बच्चों को लगातार थेरेपेटिक डोज देने की जानकारी ली।

जागरूकता रथ को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना

बैतूल (निप्र)। विश्व मलेरिया दिवस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज कुमार हुरमाड़े द्वारा शनिवार को सीएमएचओ कार्यालय से हरी झण्डी देकर मलेरिया रथ को रवाना किया गया। सीएमएचओ डॉ हुरमाड़े ने बताया कि मलेरिया एक संक्रामक रोग है, जो संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया 5 प्रकार का होता है। बैतूल जिले में प्रमुखतः 2 प्रकार का मलेरिया पाया जाता हैं, पहला है प्लाजमोडियम वाइवेक्स मलेरिया और दूसरा प्जाजमोडियम फेल्सीपेरम मलेरिया। मलेरिया के सामान्य लक्षण हैं, तेज बुखार, सर दर्द, ठंड लगना, कंपकंपी आना, पसीना आना, लेकिन गंभीर स्थिति में उल्टी होना, डायरिया तथा मरीज कोमा में भी जा सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। अतः मरीज को गंभीर स्थिति में जाने से बचाने के लिए अविलंब खून की जांच तथा मलेरिया पाए जाने पर तुरंत उपचार देना आवश्यक है। उपचार से तात्पर्य पूर्ण उपचार से है, वाइवैक्स मलेरिया में 14 दिनों तक उपचार दिया जाता है एवं फेल्सीपेरम मलेरिया में 3 दिनों तक उपचार दिया जाता है। यदि संक्रमित व्यक्ति को मादा एनाफिलीज मच्छर काट ले और यह मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटे तो मलेरिया फैल सकता

है। मच्छर के काटने से लक्षण प्रकट होने के बीच के समय को इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं तथा यह 9 से 14 दिनों तक का होता है। मलेरिया से लीवर, लाल रक्त कोशिकाएं तथा गंभीर स्थिति में किडनी एवं दिमाग भी प्रभावित होते हैं।

दूरस्थ ग्राम पंचायत फोफल्या में कलेक्टर डॉ सोनवणे ने लगाई रात्रि चौपाल

ग्रामीणों की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुन त्वरित कार्यवाही के दिए निर्देश

बैतूल (निप्र)। शाहपुर क्षेत्र के सघन भ्रमण के दौरान कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने दूरस्थ ग्राम पंचायत फोफल्या में रात्रि चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों सेआत्मीय संवाद किया और उनकी समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनीं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही त्वरित समाधान के निर्देश दिए। चौपाल में ग्रामीणों ने मोटर खराब होने से पेयजल समस्या की जानकारी दी , जिस पर कलेक्टर डॉ सोनवणे ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को तत्काल मरम्मत कर समस्या दूर करने के

निर्देश दिए। खाद की उपलब्धता को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में पर्याप्त खाद उपलब्ध है, किसानों को सही तरीके से ई विकास पोर्टल पर डिमांड दर्ज करने के लिए जागरूक किया जा रहा है, जिससे समय पर खाद वितरण सुनिश्चित हो सके। स्लॉट बुकिंग से जुड़ी समस्या का भी शीघ्र निराकरण होगा। कलेक्टर डॉ सोनवणे ने राशन और बिजली संबंधी समस्याओं की भी जानकारी ली। बिजली बाधित होने से नल-जल योजना प्रभावित होने पर एमपीईबी को आवश्यक मरम्मत कार्य कराने के निर्देश दिए गए तथा पंचायत को रूफटॉप सोलर लगाने का सुझाव दिया गया।

ग्राम खरपावाड़ी में सिंचाई समस्या के समाधान के लिए बेराज निर्माण के लिए स्थल निरीक्षण कराने के निर्देश दिए गए। वहीं खरपावाडी में जर्जर स्कूल भवन की समस्या पर नवीन कक्ष निर्माण कराने के निर्देश पंचायत को दिए गए। डोडरामहू और पांडराझिरी में भी विभिन्न समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए गए। पांडराझिरी के एक किसान के खेत में आग लगने की घटना पर कलेक्टर ने एसडीएम को पटवारी के माध्यम से जांच कराकर मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए। 'एक बगिया मां के नाम 'योजना के हितग्राही का लंबित भुगतान शीघ्र कराने के निर्देश जनपद सीईओ को दिए गए। ग्राम डाबरी में बिजली समस्या के समाधान के लिए नए पोल लगाने के प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति दिलाने तथा पुरानी बिजली लाइनों के कारण खेतों में आग लगने की समस्या को दूर करने के निर्देश दिए गए। हाई स्कूल डाबरी में नियमित महिला शिक्षक की कमी को दूर करने और गुप्तापुर में शिक्षक की अनुपस्थिति की शिकायत पर जांच कर कार्यवाही के निर्देश एसडीएम को दिए गए। कलेक्टर डॉ सोनवणे ने अन्य समस्याओं पर भी गंभीरता से सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर एसडीएम सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज सूपखार में करेंगे जंगली भैंस पुर्नस्थापन का शुभारंभ

कान्हा में लौटेंगे जंगली भैंसें, काजीरंगा से शुरू हो रहा ऐतिहासिक ट्रांसलोकेशन

एमपी-असम के बीच जुड़ रहा वन्यजीव संरक्षण और जैव-विविधता सहयोग का नया अध्याय

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि चीता पुर्नस्थापना की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब जंगली भैंसों की वापसी से प्रदेश की जैव-विविधता में एक नया आयाम जुड़ेगा। प्रदेश में एक सदी से अधिक समय से विलुप्त हो चुकी 'जंगली भैंस' (वाइल्ड बफेलो) प्रजाति की पुर्नस्थापना की रणनीति अब साकार हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव 28 अप्रैल को बालाघाट जिले के सूपखार एवं टोपला क्षेत्र में कार्यक्रम के अंतर्गत 'जंगली भैंस' पुर्नस्थापन अभियान का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री सूपखार में 4 जंगली भैंसों को उनके नए प्राकृतिक आवास में छोड़ेंगे। इनमें 3 मादा और एक नर जंगली भैंसा शामिल हैं। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह, अधिकारीगण, स्थानीय जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहेंगे। इस पहल से भैंस प्रजाति के संरक्षण के साथ ही राज्य का वन पारिस्थितिकी तंत्र भी सशक्त बनेगा।

वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता सहयोग का विस्तार

इस परियोजना के साथ ही मध्यप्रदेश और असम के बीच वन्यजीव आदान-प्रदान का नया अध्याय भी जुड़ रहा है। असम से गैंडे (राइनो) के दो जोड़े मध्यप्रदेश लाए जाएंगे, जिन्हें भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाएगा। इसके बदले में मध्यप्रदेश, असम की मांग के अनुसार 3 बाघ और 6 मगरमच्छों का स्थानांतरण करेगा। इस पर गुवाहाटी में मुख्यमंत्री डॉ. यादव और असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंता विश्व सरमा के बीच हुई बैठक में सहमति बनी थी।

काजीरंगा से कान्हा तकः ऐतिहासिक ट्रांसलोकेशन– इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत असम के काजीरंगा से जंगली भैंसों को कान्हा टाइगर रिजर्व लाया जा रहा है। पहले चरण में 4 भैंसों का दल अपनी यात्रा प्रारंभ कर चुका है। कुल 50 भैंसों के समूह को 'फाउंडर पॉपुलेशन' के रूप में लाने का लक्ष्य निर्धारित है। इस सीजन में 8 भैंसों को स्थानांतरित किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया काजीरंगा और कान्हा के वरिष्ठ अधिकारियों एवं अनुभवी पशु-चिकित्सकों की निगरानी में वैज्ञानिक तरीके से संपन्न की जा रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि चीता पुर्नस्थापना के बाद अब जंगली भैंसों की वापसी से प्रदेश की जैव-विविधता में एक नया आयाम जुड़ेगा।

यह पहल एक प्रजाति के संरक्षण के प्रयास के साथ ही प्रदेश के वन पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। मध्यप्रदेश पहले ही 'टाइगर स्टेट' और 'लेपर्ड स्टेट' के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुका है। जंगली भैंसों का पुनर्स्थापन इस गौरव को और सुदृढ़ करेगा।

प्रकृति संतुलन की दिशा में निर्णायक पहल– सूपखार में जंगली भैंसों को छोड़े जाने के साथ यह 'वाइल्ड-टू-वाइल्ड' पुनर्स्थापना परियोजना एक नए चरण में प्रवेश करेगी। विशेषज्ञों के अनुसार, इससे कान्हा की घासभूमि पारिस्थितिकी को मजबूती मिलेगी और जैव-विविधता संतुलन को नया जीवन मिलेगा। यह पहल मध्यप्रदेश वन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में संचालित एक और ऐतिहासिक संरक्षण अभियान है, जो आने वाले समय में देश के लिए एक मॉडल के रूप में स्थापित होगा।

महत्वपूर्ण है यह पुर्नस्थापन

मध्यप्रदेश में जंगली भैंसों की आबादी लगभग 100 वर्ष पहले समाप्त हो गई थी। कान्हा के सूपखार क्षेत्र में 1979 के आसपास जंगली भैसा देखा गया था। अत्यधिक शिकार, मानव हस्तक्षेप, आवास का क्षरण और घास के मैदानों का नष्ट होना इसके प्रमुख कारण रहे। वर्तमान में इनकी प्राकृतिक आबादी मुख्य रूप से असम में सीमित है, जबकि छत्तीसगढ़ में इनकी संख्या अत्यंत कम है।

कान्हा सबसे उपयुक्त प्राकृतिक आवास

भारतीय वन्यजीव संस्थान (देहरादून) द्वारा किए गए अध्ययन में कान्हा टाइगर रिजर्व को जंगली भैंसों के पुर्नस्थापन के लिए सबसे उपयुक्त पाया गया है। यहाँ के विस्तृत घासभूमि क्षेत्र, पर्याप्त जल स्त्रोत और न्यूनतम मानव हस्तक्षेप इस प्रजाति के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं।

लव-मैरिज के 7 महीने बाद युवक का सुसाइड

इंस्टाग्राम वीडियो में कहा–पत्नी करती थी प्रताड़ित

भोपाल। भोपाल में एक युवक ने पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर अपनी जान दे दी। सुसाइड से पहले युवक ने वीडियो रिकॉर्ड कर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया। इसमें पत्नी और ससुरालवालों पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए। मामला शाहपुरा के कान्वेवेल होटल पैलेस में रविवार सुबह का है। मृतक की पहचान विकास हिरवे (28) के रूप में हुई। वह हबीबगंज क्षेत्र का रहने वाला था। 7 महीने पहले ही उसने लव मैरिज की थी। दोपहर में युवक का पोस्टमॉर्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया। पुलिस वीडियो की जांच कर रही है।

होटल में कमरा बुक कर की आत्महत्या

पुलिस के मुताबिक, विकास ने शनिवार देर रात होटल में कमरा बुक किया था। रविवार सुबह होटल स्टाफ ने कमरे में उसका शव फांसी के फंदे पर लटका पाया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन परिजनों ने एक वीडियो पुलिस को सौंपा है। पुलिस वीडियो की जांच कर रही है। युवक ने सुसाइड से पहले वीडियो में यह कहा- मेरा नाम विकास हिरवे है। मेरी पत्नी स्नेहा सोलंकी से 7 माह पहले लव मैरिज की थी। मैं मनमर्जी से सुसाइड कर रहा हूं... इसकी जिम्मेदार पत्नी स्नेहा सोलंकी है। 10 दिन पहले से स्नेहा ने अपने तमाम डॉक्यूमेंट, ज्वेलरी सहित सामान को अपने मायके में भेजना शुरू कर दिया था। वह लगातार मुझसे विवाद करती है। प्रताड़ित करती है और फंसाने की धमकी देती है। उसकी दादी लगातार उसे कॉल कर यह सब करने के लिए मजबूर करती है। ससुरालवालों की प्रताड़ना से तंग आकर ही मैं जान दे रहा हूं। मेरी मौत के लिए जिम्मेदार मेरी पत्नी और दादी सास हैं।

पत्नी से विवाद के बाद घर से निकला था

परिजनों ने पुलिस को बताया कि शनिवार शाम को पति-पत्नी के बीच मामूली कहासुनी हुई थी। इसके बाद रात के समय युवक बिन बताए घर से निकला। तड़के करीब 3:00 बजे उसकी आखिरी पोस्ट को देखा। इसके बाद उसकी तलाश शुरू की। जब होटल पहुंचे तो वहां युवक सुसाइड कर चुका था। आखिरी वीडियो में युवक ने इस बात का भी जिक्र किया है कि पत्नी को परिवार वाले बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वह इसके बाद भी मुझे और उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी देती है।

भोपाल मंडल के रेल यात्रियों के लिए अलर्ट, 10 ट्रेनों का रूट बदला, कई स्टेशनों पर ठहराव प्रभावित

भोपाल। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों के यात्रियों के लिए अहम सूचना है। उत्तर रेलवे के जौनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग का बड़ा काम शुरू होने जा रहा है, जिसके चलते कई ट्रेनों के मार्ग में अस्थायी बदलाव किया गया है। यह काम 4 मई से 27 मई 2026 तक लगभग 24 दिनों तक चरणबद्ध तरीके से चलेगा। इस दौरान भोपाल मंडल होकर चलने वाली 10 ट्रेनों को जौनपुर के बजाय वैकल्पिक मार्ग से चलाया जाएगा।

इन 10 ट्रेनों का बदला रूट

- गाड़ी संख्या 19051 वलसाड-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस 16 और 23 मई को परिवर्तित मार्ग से चलेगी
- गाड़ी संख्या 19052 मुजफ्फरपुर-वलसाड एक्सप्रेस 18 और 25 मई को परिवर्तित मार्ग
- गाड़ी संख्या 11056 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27 मई
- गाड़ी संख्या 11060 लोकमान्य तिलक-गोरखपुर एक्सप्रेस 14, 16, 18, 21, 23, 25 मई
- गाड़ी संख्या 11055 छपरा- लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25 मई
- गाड़ी संख्या 11059 लोकमान्य तिलक-छपरा एक्सप्रेस 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26 मई
- गाड़ी संख्या 19045 सूरत-थावे ताप्ती गंगा एक्सप्रेस 03, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25 मई
- गाड़ी संख्या 19046 थावे-सूरत ताप्ती गंगा एक्सप्रेस 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27 मई
- गाड़ी संख्या 19321 इंदौर- पटना एक्सप्रेस 09, 16, 23 मई
- गाड़ी संख्या 22103 लोकमान्य तिलक-अयोध्या कैंट एक्सप्रेस 18 और 25 मई

मध्यप्रदेश की 'बाग प्रिंट' कला को पेरिस में मिलेगा वैश्विक मंच

अन्तर्राष्ट्रीय मेले फोयर डे पेरिस में होगी प्रदर्शित

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में पारंपरिक हस्तशिल्प और स्थानीय कला को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिये निरंतर प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश की विशिष्ट 'बाग प्रिंट' कला को फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित मेले 'फ़ोयर डे पेरिस' में प्रदर्शित किया जायेगा। यह मेला 30 अप्रैल से 11 मई 2026 तक पेरिस के पोर्टे डे वर्साय प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित किया जाएगा। केन्द्रीय वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा देशभर से चयनित पांच श्रेष्ठ शिल्पकारों में प्रदेश के नेशनल अवार्डी शिल्पकार मोहम्मद बिलाल खत्री को शामिल किया गया है। वे इस मेले में प्रदेश की 'बाग प्रिंट' कला का प्रतिनिधित्व करते हुए मास्टर क्राफ्ट्समैन के रूप में शामिल होंगे। 'बाग प्रिंट' हस्तशिल्प भौगोलिक संकेत (ळढ़) के अंतर्गत संरक्षित है।

लाइव डेमोंस्ट्रेशन से रूबरू होंगे दर्शक– इस अन्तर्राष्ट्रीय मेले में बिलाल खत्री 'बाग प्रिंट' कला का लाइव प्रदर्शन करेंगे। पारंपरिक प्राकृतिक रंगों, नक्काशीदार लकड़ी के ब्लॉक्स और हस्तनिर्मित तकनीकों के माध्यम से कपड़ों पर उभरती कलाकृतियों को अन्तर्राष्ट्रीय दर्शक प्रत्यक्ष देख सकेंगे। यह भारतीय हस्तशिल्प की गहराई और सौंदर्य को समझने का अनूठा अवसर प्रदान करेगा।

परंपरा और आधुनिकता का संतुलित समावेश–इस विशेष प्रदर्शनी के लिए तैयार किए गए डिज़ाइन में भारतीय पारंपरिक शिल्प और आधुनिक वैश्विक सौंदर्यबोध का समन्वय किया गया है। यूरोपीय बाज़ार की पसंद को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई ये कृतियां 'बाग प्रिंट' को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान देंगी।

'बाग प्रिंट' की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि– 'बाग प्रिंट' मध्यप्रदेश के धार जिले के बाग क्षेत्र की पारंपरिक हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग कला है। बाग एक छोटा जनजातीय कस्बा है, जहां भील और भिलाला समुदाय निवास करते हैं और प्राचीन बाघ गुफाएं भी स्थित हैं। इस कला की परंपरा खत्री समुदाय द्वारा लगभग 400 वर्ष पूर्व सिंध के लरकाना क्षेत्र से आकर स्थापित की गई मानी जाती है।

इस शिल्प में सूती और रेशमी कपड़ों को पारंपरिक प्राकृतिक प्रक्रियाओं से तैयार किया जाता है। लोहे के संक्षारण, धवाड़ी फूल और मायरोबालन के मिश्रण के साथ-साथ फिटकरी और एलिज़ारिन का उपयोग किया जाता है। कुशल कारीगरों द्वारा लकड़ी के ब्लॉक्स से डिज़ाइन तैयार कर उन्हें हाथ से भरा जाता है। तैयार वस्त्रों को बहते पानी में धोकर धूप में सुखाया जाता है, जिससे उन्हें विशिष्ट फिनिश प्राप्त होती है। 'बाग प्रिंट' में लाल और काले रंग के ज्यामितीय एवं पुष्पीय रूपांकन प्रमुख होते हैं।

एमपी में शिक्षकों को राहतः कोर्ट ने प्रमोशन प्रक्रिया को दी पहली प्राथमिकता, पहले पदोन्नति फिर होंगे ट्रांसफर

भोपाल। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के ताजा और सख्त निर्देशों ने मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली को पूरी तरह बदलने का संकेत दे दिया है। अदालत ने स्पष्ट और कड़े शब्दों में कहा है कि पदोन्नति, स्थानांतरण (ट्रांसफर) और अतिशेष (सरप्लस) की प्रक्रिया अब किसी भी हालत में मनमाने ढंग से नहीं चल सकती। इसके लिए एक तय क्रम अपनाना होगा, जिसमें सबसे पहले पदोन्नति को प्राथमिकता दी जाएगी। यह आदेश ऐसे समय आया है जब विभाग में लंबे समय से पदोन्नति और ट्रांसफर को लेकर असमंजस और असंतोष का माहौल बना हुआ था। अब कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पूरे सिस्टम में तेजी से बदलाव की स्थिति बन गई है।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के ताजा और सख्त निर्देशों ने मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली को पूरी तरह बदलने का संकेत दे दिया है। अदालत ने स्पष्ट और कड़े शब्दों में कहा है कि पदोन्नति, स्थानांतरण (ट्रांसफर) और अतिशेष (सरप्लस) की प्रक्रिया अब किसी भी हालत में मनमाने ढंग से नहीं चल सकती। इसके लिए एक तय क्रम

अपनाना होगा, जिसमें सबसे पहले पदोन्नति को प्राथमिकता दी जाएगी। यह आदेश ऐसे समय आया है जब विभाग में लंबे समय से पदोन्नति और ट्रांसफर को लेकर असमंजस और असंतोष का माहौल बना हुआ था। अब कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पूरे सिस्टम में तेजी से बदलाव की स्थिति बन गई है।

30 दिन की डेडलाइन– हाईकोर्ट ने सिर्फ दिशा-निर्देश ही नहीं दिए, बल्कि एक सख्त समयसीमा भी तय की है। अदालत ने कहा है कि आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के 30 दिनों के भीतर पूरी पदोन्नति प्रक्रिया खत्म की जाए। इसमें उच्च पदों पर कार्यवाहक नियुक्ति और प्रभार देने की प्रक्रिया भी शामिल है। यानी विभाग को तय समय के भीतर तेजी से काम करना होगा, वरना जवाबदेही तय होना तय माना जा रहा है।

प्रभार देने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के निर्देश– कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उच्च पदों पर कार्यवाहक नियुक्ति और प्रभार देने में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। यह प्रक्रिया नए नियमों से प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि उन पर फिलहाल रोक लगी है। हालांकि अदालत ने यह भी कहा है कि इन पदोन्नतियों और प्रभार का अंतिम स्वरूप याचिका के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।

शिक्षक संगठनों की चेतावनी

अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के सदस्य उपेंद्र कौशल ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर प्रक्रिया का सही क्रम नहीं अपनाया गया, तो इसका सीधा असर हजारों शिक्षकों पर पड़ेगा। उनका कहना है कि सबसे पहले पदोन्नति और प्रभार की प्रक्रिया पूरी हो उसके बाद ही ट्रांसफर किए जाएं अंत में अतिशेष (सरप्लस) की कार्रवाई की जाए अगर इस क्रम को उलट दिया गया, तो कई पदों पर असंतुलन पैदा होगा, योग्य शिक्षकों को नुकसान होगा और बाद में स्थिति को सुधारना मुश्किल हो जाएगा।

सरकार पर बढ़ा दबाव, आंदोलन की भी चेतावनी

शिक्षक संगठनों ने सरकार से मांग की है कि हाईकोर्ट के आदेश का पूरी पारदर्शिता के साथ पालन किया जाए। उन्होंने साफ कहा है कि अगर आदेश के मुताबिक कार्रवाई नहीं हुई, तो वे आंदोलन का रास्ता भी अपना सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब सरकार और शिक्षा विभाग दोनों पर दबाव बढ़ गया है कि वे समयसीमा और तय प्रक्रिया का सख्ती से पालन करें।

रसूखदार सीनियर IAS के दिल्ली जाने की चर्चा!

मोहन का मंत्रालय

आशीष चौधरी

मध्य प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों 'दिल्ली चलो' के नारों की गूँज है। चर्चा है कि एक रसूखदार सीनियर आईएएस साहब, जो वर्तमान में 'एक्सटेंशन' पर हैं, उनका मन अब विंध्य की पहाड़ियों से भर गया है। सूत्र कह रहे हैं कि साहब का एक्सटेंशन खत्म होने से पहले ही दिल्ली दरबार ने उन्हें 'न्योता' भेज दिया है। साहब ने भी बिना देर किए 'कुबूल है' कह दिया और सूबे के मुखिया को अवगत करा दिया कि अब वे बड़े कैनवास पर अपनी कलम चलाएंगे। सूत्र यह भी बताते हैं कि अगले माह प्रदेश में यदि यह स्थिति रही तो बड़ा प्रशासनिक फिर बदल होगा। साहब के जाते ही वल्लभ भवन में चेहरों की कतार बदल जाएगी। कई जो 'लाइन' में लगे हैं, उनकी लॉटरी खुलने वाली है। खैर, साहब दिल्ली में सेटल होंगे या रिटायरमेंट के बाद का कोई नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं, यह तो वक्त बताएगा।

'सोना' पड़ा महंगा

गर्मी के इस प्रचंड मौसम में वल्लभ भवन के एनेक्सी के केंद्रीकृत वातानुकूलित हाल की ठंडी हवाएं किसी स्वर्ग से कम नहीं लगतीं। लेकिन कुछ कर्मचारियों ने इस 'राहत' को अपनी व्यक्तिगत 'रियासत' समझ लिया। मंत्रालय के चमचमाते सोफों को कुछ मुलाजिमों ने अपना बेडरूम बना लिया और खर्राटे भरने लगे। अब जब खर्राटों की गूँज साहबों के कानों तक पहुँची, तो डंडा चल गया। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने 'स्लीपिंग एम्पाइज' को जगाया और सीधे रू. 500 का रसीद थमा दिया। दर्जनों कर्मचारियों की जेब ढीली हो चुकी है। अब बेचारे कर्मचारी एसी की हवा तो खा रहे हैं, लेकिन आंखें फाड़कर, क्योंकि यहाँ नींद का मतलब 'ड्रीम्स' नहीं, बल्कि 'डेबिट' है।

रील वाले 'कलेक्टर साहब' और जमीन वाला दिखावा

आजकल ब्यूरोक्रेसी पर 'रील' का भूत सवार है। प्रदेश के चाहे मालवा के साहब हों या विंध्य के, जनसुनवाई कम और 'शूटिंग' ज्यादा हो रही है। कई जिलों के कलेक्टर साहबान जनता की समस्याएं सुनने के लिए जमीन पर ऐसे बैठ रहे हैं, मानो साक्षात 'सेवक' का अवतार ले लिया हो। कैमरा एंगल सही होना चाहिए, बस फिर क्या... जनसेवा की रील तैयार! मंत्रालय में बैठे पुराने और गंभीर आईएएस इस तमाशे से खफा हैं। उनका कहना है कि 'साहब' अपनी गरिमा का ध्यान रखें, रील के चक्कर में 'रियल' ब्यूरोक्रेसी को शर्मिंदा न करें। अब साहबों को कौन समझाए कि आज के दौर में काम दिखे न दिखे, 'अपलोड' जरूर होना चाहिए!

दर्शक दीर्घा, सेल्फी और मेयर की मेहनत

महिला आरक्षण के विशेष सत्र में सोमवार को विधानसभा की दर्शक दीर्घा 'हाउसफुल' थी। इस भीड़ को जुटाने का जिम्मा भोपाल की महापौर को मिला था, जिन्होंने जिम्मेदारी बखूबी निभाई। दर्शक दीर्घा में महिलाओं की फौज तो खड़ी हो गई, लेकिन लोकतंत्र की गरिमा और भारी-भरकम चर्चाओं के बीच बेचारा 'धैर्य' जवाब दे गया। सदन में जब चर्चा लंबी खिंची, तो महिलाएं बोरियत मिटाने के लिए विधानसभा को 'पिकनिक स्पॉट' समझ बैठीं। आरक्षण पर बहस जारी थी और विधानसभा परिसर में सेल्फी का दौर चल रहा था। शाम होते-होते 'क्रांतिकारी' महिलाएं घर की ओर रवाना हो गईं, पीछे छोड़ गईं खाली कुर्सियां और महापौर की मेहनत के किस्से।

मध्यप्रदेश में श्रम स्टार रेटिंग पहल को मिल रही व्यापक स्वीकृति

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभाग द्वारा संचालित श्रम स्टार रेटिंग पहल को प्रदेशभर में उद्योगों से सकारात्मक प्रतिसाद मिल रहा है। इस पहल का उद्देश्य कारखानों में श्रम कानूनों के पालन को सुनिश्चित करना तथा श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण से जुड़ी सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना है। संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मध्यप्रदेश इंदौर श्रीमती नमिता तिवारी ने बताया है कि अब तक प्रदेश के 554 कारखानों ने स्व-मूल्यांकन के माध्यम से श्रम स्टार रेटिंग प्राप्त की है। इनमें बड़ी, मध्यम और लघु श्रेणी की विभिन्न विनिर्माण इकाइयाँ शामिल हैं, जो इस पहल की व्यापक स्वीकार्यता और औद्योगिक क्षेत्रों में इसके प्रभावी प्रसार को दर्शाती हैं। श्रम स्टार रेटेड कारखाने इस बात का प्रमाण होते हैं कि संबंधित कार्यस्थलों पर बाल श्रम और बंधुआ श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित हैं तथा श्रमिकों के अधिकारों का समुचित संरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है। संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा इंदौर ने इस पहल में सक्रिय सहभागिता के लिए सभी कारखानों का आभार व्यक्त किया है। विशेष रूप से, श्रम स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाले पहले पाँच कारखानों की सराहना की गई है, जिन्होंने इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभाते हुए सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत किया। इस प्रणाली को अपनाने से न केवल श्रमिकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, बल्कि उद्योगों को भी कई प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होते हैं। इससे उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ता है, निवेशकों का भरोसा मजबूत होता है और बाजार में संस्थानों की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। साथ ही, प्रमाणित कारखानों को उपभोक्ताओं द्वारा प्राथमिकता मिलने की संभावना भी अधिक रहती है, जिससे उनकी ब्रांड वैल्यू और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मजबूत होती है।